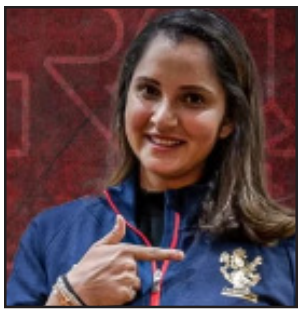

टेनिस से सन्यास लेने ...

न्यायपथ

इमरान खान को जाना ...

वर्ष : 13 अंक-27 प्रयागराज साप्ताहिक शुक्रवार 17 फरवरी 2023 से 23 फरवरी 2023 मुद्रित पृष्ठ-8 मूल्य-2 रुपये

आदिवासी समाज से दुनिया को सीखने की जरूरत:पीएम मोदी

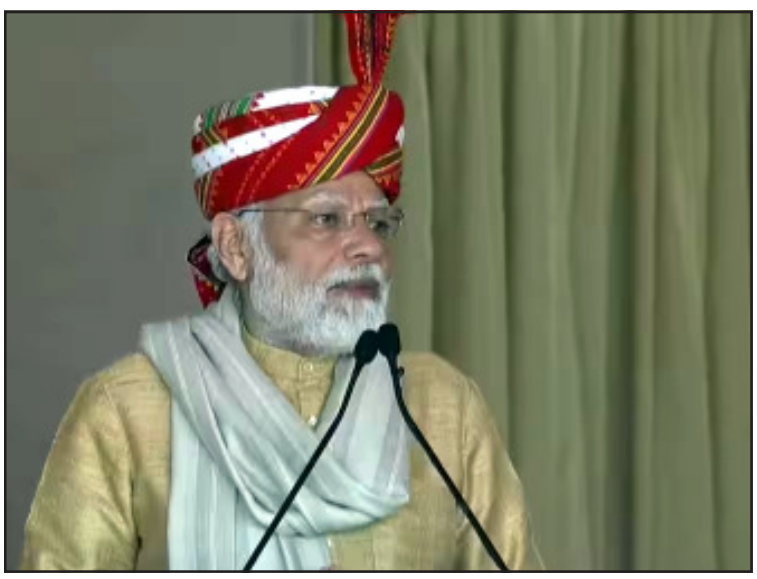

नई दिल्ली (वेब वार्ता)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली की मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आदि महोत्सव देश की व्यवस्था की पहचान है। उन्होंने कहा कि हाशिए पर पड़े लोगों को मुख्यधारा में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासियों को लेकर देश गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आदिवासी जीवनसैली ने बहुत कुछ सिखाया है। यहां की परंपरा से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। आदि महोत्सव एक भारत-श्रेष्ठ भारत का स्वरूप है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह महोत्सव अब एक अभियान बन गया है। आदिवासी परंपरा को गौरव के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। साथ-साथ मोदी ने यह भी कहा है कि आदिवासी समाज से दुनिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। 'आदि महोत्सव' की शुभकामनाएं देते हुए मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की अनेकता और भव्यता आज एक साथ खड़ी हो गई हैं। यह भारत के उस अनंत आकाश की तरह है जिसमें उसकी विविधताएं इंद्रधनुष की तरह उभर कर सामने आ जाती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह अनंत विविधताएं हमें एक भारत-श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं। पीएम ने कहा कि उनके उत्पादों के माध्यम से विभिन्न कलाओं, कलाकृतियों, संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगता है कि भारत की विविधता और इसकी भव्यता एक साथ आ गई है और आज इसकी परंपरा को उजागर कर रही है। उन्होंने कहा कि जब विविधताओं को एक भारत-श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरोया जाता है, तो भारत की भव्यता दुनिया के सामने उभरती है। यह आदि महोत्सव इसी भावना का प्रतीक है।नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर-सुदूर समझता था अब सरकार उसके द्वार जा रही है, उसको मुख्यधारा में ला रही है। आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत 'सबका साथ सबका विकास' के दर्शन पर काम कर रहा है। सरकार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। मोदी ने कहा कि मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। आदिवासियों की जीवनशैली ने मुझे देश की विरासत और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आपके बीच आकर मुझमें अपनों से जुड़ने का भाव आता है।

जल रहेगा तभी आने वाला कल रहेगा : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली(वेब वार्ता)।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित जलजन अभियान का उद्घाटन किया। इस दौरान मोदी ने कहा कि जल रहेगा तभी आने वाला कल रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं जब भी आपके पास आता हूं आपका स्नेह और अपनापन मुझे अभिभूत कर देता है। मोदी ने कहा कि जल जन अभियान एक ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पानी की कमी को भविष्य के संकट के रूप में देखा जा रहा है। इतनी बड़ी आबादी के कारण 'वाटर सिक्योरिटी' हम सब की साझी जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल रहेगा तभी आने वाला कल भी रहेगा और इसके लिए हमें आज से ही प्रयास करने होंगे।मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में आज देश जल को कल के रूप में देख रहा है। उन्होंने संतोष जताते हुए कहा कि जल संरक्षण के संतोष को अब देश जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ा रहा है। ब्रह्म कुमारी संस्थान के इस जल जन अभियान से जन भागीदारी के इन प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण पर जड़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इस से जल संरक्षण के अभियान की पहुंच भी बढ़ेगी और प्रभाव भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारियों के साथ मेरा रिश्ता बहुत खास है क्योंकि खुद पर काबू पाना और समाज को सब कुछ समर्पित करना आध्यात्मिकता खोजने का एक तरीका रहा है। समाज के लिए यह निःस्वार्थ सेवा सभी को प्रेरित करती रहती है।नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में दुनिया समझ गई है कि जल संसाधन सीमित हैं और जल सुरक्षा की आवश्यकता सभी की जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि हमारा भविष्य पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है और मुझे खुशी है कि पूरा देश जल संरक्षण को एक आंदोलन के रूप में ले रहा है। उन्होंने दावा किया कि आज ना केवल गंगा साफ हो रही है बल्कि उनकी तमाम सहायक नदियां भी स्वच्छ हो रही हैं। गंगा के किनारे प्रकृतिक खेती जैसे अभियान भी शुरू हुए हैं। जल प्रदूषण की तरह ही, गिरता भू जल स्तर भी देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

कश्मीर में पहले हर दिन होता था विरोध प्रदर्शन और पथराव, आज पर्यटकों से भरा है : शाह

नई दिल्ली (वेब वार्ता)।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले हर दिन वहां विरोध प्रदर्शन और पथराव होता था। लेकिन आज वहां की स्थिति में परिवर्तन आया है और आज कश्मीर पर्यटकों से भरा हुआ है। दरअसल, अमित शाह दिल्ली पुलिस के 76 वें स्थापना दिवस परेड को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए गर्व का क्षण है कि मैं 75 साल से अधिक की विरासत का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस आजादी के बाद से आज तक अपने काम के लिए जानी जाती है और पूरे देश ने इसकी सराहना की है। गृह मंत्री ने उन लोगों के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी। शाह ने कहा कि आजादी के बाद दिल्ली पुलिस शांति, सेवा, न्याय के नारे के साथ आगे बढ़ी और अपने काम और कार्यप्रणाली में बदलाव लाया है जो देश के लिए फायदेमंद है। उन्होंने दावा किया कि भारत की कानून और व्यवस्था, सुरक्षा में 2014 से सकारात्मक विकास देखा गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले भारत के नागरिकों को अपने पासपोर्ट के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उन्हें 5 दिनों के भीतर पुलिस की मंजूरी मिल जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस के लिए वर्ष 2023 बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि भारत दिल्ली में 320 की मेजबानी कर रहा है। इसके साथ ही अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में हर दिन विरोध, पथराव और क्रांति का स्थान हुआ करता था। आज कश्मीर पर्यटकों से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि जब हम देश भर में यात्रा करते हैं तो कश्मीर के बारे में सोचते हुए हम बहुत सशक्त महसूस करते हैं। वामपंथी राजनीति और उग्रवाद के मामले अब काफी कम हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले दिनों में दण्ड, दंड और साक्ष्य अधिनियम वाले तीनों कानूनों में परिवर्तन लाने जा रही है... हमने दिल्ली पुलिस में ट्रायल शुरू किया है कि 6 साल से ज्यादा सजा वाले हर अपराध में फोरेंसिक टीम के दौरे को हम अनिवार्य करने जा रहे हैं।

टीपू सुल्तान पर गरमाई सियासत, कटील के बयान पर भड़के ओवैसी

नई दिल्ली (वेब वार्ता)।कर्नाटक में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने है। विधानसभा चुनाव को लेकर अब ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई है और चर्चा के केंद्र में टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान का मुद्दा कर्नाटक में लगातार गर्म होता जा रहा है। दरअसल, बुधवार को कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने टीपू सुल्तान को लेकर एक बयान दे दिया था। इसके बाद ओवैसी ने भड़कते हुए पलटवार किया है। ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, देखता हूं आप क्या करते हो। दरअसल, कटील ने कहा था कि टीपू सुल्तान के अनुयायियों को यहां रहने का हक नहीं। उन्हें जंगलों में खदेड़ देना चाहिए।

इसी को लेकर ओवैसी का बयान सामने आया है। ओवैसी ने सवाल किया कि क्या कर्नाटक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जो कहा है उसे प्रधानमंत्री मोदी सहमत है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह हिंसा, हत्या और नरसंहार का खुला ऐलान है। क्या कर्नाटक में भाजपा सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी? ओवैसी ने कटील के बयान को नफरत फैलाने वाला बयान बताया। दूसरी ओर भाजपा ने भी अब ओवैसी पर पलटवार किया है। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि टीपू सुल्तान का विचार गलत था। नलिन कुमार कटील के बयान बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवी ने कहा कि टीपू सुल्तान का विचार गलत विचार है। वे कन्नड के विरोधी विचार हैं। इस्लामिक स्टेट करना उनका विचार है। सभी काफिरों का कत्ल टीपू सुल्तान का विचार है उनके विचार जिंदा नहीं रहने चाहिए। आपको बता दें कि कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने फिर से टीपू सुल्तान का मुद्दा छेड़ दिया था। इसके साथ ही उन्होंने खुद को भगवान राम और हनुमान का भक्त बताया। अपने बयान में नलिन कुमार ने कहा कि हम भगवान राम और हनुमान के भक्त हैं। हम टीपू के वंशज नहीं हैं, हमने उनके वंशजों को वापस भेज दिया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष ने हुंकार भरते हुए कहा कि मैं येलबुर्गा के लोगों से पूछता हूं, क्या आप हनुमान की पूजा करते हैं या टीपू के भजन गाते हैं? क्या आप टीपू के भजन गाने वाले लोगों को भगाएंगे? इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तो सोचिए कि इस राज्य को टीपू के वंशज चाहिए या भगवान राम

और हनुमान के भक्तों की? इसके साथ ही उन्होंने चुनौती भी दी। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान की धरती पर चुनौती देता हूं- टीपू से प्यार करने वालों को यहां नहीं रहना चाहिए, भगवान राम के भजन गाने वाले और भगवान हनुमान को मनाने वाले यहां रहें। इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और जनता दल (सेक्युलर) 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान में विश्वास रखते हैं और दोनों दल कर्नाटक का भला नहीं कर सकते हैं।

मुक्त विवि के रोजगार मेला में 123 को मिली नौकरी

प्रयागराज(नि.सं)। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने चयनित 123 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कुलपति के हाथ से नियुक्ति पत्र मिलते ही सभी अभ्यर्थी खुशी से झूम उठे। रोजगार मेला को सम्बोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि यह हम सब की जीत है। हमारे विद्यार्थियों को नौकरी मिली है और कम्पनियों को भी योग्य अभ्यर्थी प्राप्त हुए हैं। उन्होंने चयनित छात्र-छात्राओं को बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की और कम्पनियों के प्रतिनिधियों को साधुवाद देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में अगली बार वृहद स्केल पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि कुलपति के प्रयासों से विश्वविद्यालय की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पहली बार देश की जानी-मानी कम्पनियां मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित वृहद रोजगार मेले में आयीं। जिसमें जिला सेवायोजन अधिकारी के सहयोग से युवाओं को वृहद रोजगार मिलने की सम्भावना बढ़ गई। जिला सेवायोजन कार्यालय की तरफ से भी कई कम्पनियों ने रोजगार मेले में प्रतिभाग किया। जिनमें प्रमुख रूप से पीपल ट्री, रेडेक्स इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, गोल्डन फॉर्म ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रा लि तथा रूपम ट्रांसपोर्टेशन प्रा लि सहित एयर इंडिया, बाईजूस, टेक महिंद्रा, पेटीएम, एचडीबी फाइनेंसियल सर्विसेज, पैसा बाजार, योकोहोमा टायर्स, कार्ड एक्सपर्टाइज इंडिया प्रा.लि, कोटक महिंद्रा बैंक तथा हिंदुस्तान वेलनैस कंपनी के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागियों का साक्षात्कार लिया। कुलसचिव विनय कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय ने पहली बार इतने वृहद स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया है। भविष्य में विश्वविद्यालय अपने छात्रों को रोजगार देने के लिए बड़ी-बड़ी कम्पनियों को आमंत्रित करेगा। प्रशिक्षण एवं सेवा स्थापना प्रकोष्ठ के प्रभारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जीवन में गति का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्वविद्यालय ने यह प्लेटफार्म युवाओं को गति देने के लिए ही उपलब्ध कराया है। यहां वे अपने सपनों को साकार करेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। पीआरओ डॉ प्रभात चंद्र मिश्र ने बताया कि रोजगार मेला में 665 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें 310 उपस्थित हुए।

देश के उभरते सितारों में नया कीर्तिमान रचते नायर

यूरोपीय यूनियन -ब्रिटेन से ब्यापारिक सम्बंधों पर सम्मानित

प्रयागराज। विश्व में इन दिनों तेजी से बढ़ता भारत जहां नित्य नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है वहीं देश की युवा प्रतिभाएं कुछ करने को बेताब है इनहीं प्रतिभाओ में से एक केरल के सुजीत.एस.नायर जो यूरोपी यूनियन के देशों एवं ब्रिटेन , यूके के विदेश ब्यापार संबधों को प्रगाढ करने के साथ ही देश को मजबूती प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे नायर ने न्यायपथ संवाददाता को संसद भवन के पास एक संक्षिप्त मुलाकात में जानकारी दिया। श्री नायर ने न्यायपथ संवाददाता से देश के विकास में विदेशों से उनके द्वारा अब तक किये गये प्रयासों के बावत पूरे गये एक सवाल के जवाब में बताया कि वे विगत ग्यारह वर्षो से भारत की यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन, यूके की विदेश नीति से जूड़े हुए हैं और अब तक मैंने 25 ब्यापारिक सम्मेलनों का आयोजन किया हैं जिसमें 22 ब्रिटिश संसद में तथा तीन यूरोपियन संसद में आयोजित हुई जिसमें 2000 संस्थाओं की ओर से लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया । इन सम्मेलनों की सफलता के बावत पूछे जाने पर श्री नायर ने बताया कि मेरे अथक प्रयासों से प्रभावित लार्ड स्वराज पॉल ब्रिटेश सांसद ने 2014 में सम्मानित किया। श्री नायर ने न्यायपथ संवददाता से देश को विदेशों ब्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने वाले प्रयासों के बावत पूछे गये एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि यूएस डिर्पाटमेंट आफ स्टेट, अमेरिकी गृहमंत्रालय द्वारा आयोजित ग्लोबल इंटरपेन्योरशिप समिट 2015 जो यूनाइटेड नेशन के नैरोबी कार्यालय में आयोजित किया गया था। उसमें मैं विशेष प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का आयोजन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा और कीनिया के राष्ट्रपति श्री ओहरू केन्याहत्ता द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। अब तक की अन्य उपलब्धियों के बावत न्यायपथ द्वारा पूछे जाने पर श्री नायर ने बताया कि उन्हें 33 वर्ष से कम आयु के विदेश नीति में प्रभावी योगदान देने वाले विश्व में सर्वोच्च 99 में लोगों में भी सन् 2013 में चयनित किया गया। श्री नायर ने बताया कि अब तक प्रयासों से काफी सन्तुष्ट हैं लेकिन देश के उत्थान में अग्रणीय भूमिका निभाने के लिए अभी बहुत कुछ करने के लिए प्रयासरत हें।

भारतीय लोकतंत्र में हो गांधी दृष्टि का स्वराज : नंदकिशोर आचार्य

प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के प्रथम दिन नंदकिशोर आचार्य ने कहा कि गांधी के स्वराज को लोकतंत्र के मजबूती हेतु उपयोग में लाए जाने की जरूरत है। स्वराज का अर्थ सरकार के नियंत्रण से मुक्त होने का सतत प्रयास, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र अभिव्यक्ति महसूस कर सके।

उद्घाटन सत्र में जयपुर से आए प्रख्यात गांधीवादी लेखक और हिंदी के वरिष्ठ कवि नंदकिशोर आचार्य ने कहा कि आज लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र होने से पहले नैतिक लोकतंत्र की ओर ले चलना होगा। लोकतंत्र में सत्ता का रूपांतरण नागरिक दमन की ओर नहीं जाना चाहिए। लोकतंत्र की सशक्तिकरण में अधिकार का त्याग हो सकता है किंतु कर्तव्य का कदापि नहीं होना चाहिए।

दिल्ली से आए सुपरिचित साहित्यकार गोपेश्वर सिंह ने लोकतंत्र के विस्तार और विकास को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि गांधी की राजनीति आचरण की राजनीति है, उसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। जैसे भक्त कवियों की रचनाओं को उनके जीवन से अलग करके नहीं देखा जा सकता। कहा कि गांधी का लोकतंत्र अभय का लोकतंत्र था।

गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान के निदेशक और संगोष्ठी के संयोजक प्रो. संतोष भदौरिया ने संस्थान की गतिविधियों और संगोष्ठी के वैचारिकी को परिभाषित किया। इस सत्र का संचालन डॉ. अमृता ने किया।

प्रथम सत्र में 'आज़ादी के पचहत्तर सालः भारत निर्माण के वैचारिक आयाम' विषय पर मुख्य वक्तव्य देते हुए बिहार के पटना से आए वरिष्ठ लेखक और संस्कृतिकर्मी प्रेम कुमार मणि ने वैचारिक स्तर पर भारत के बनने की कहानी को अनेक कथाओं के जरिए बताया। कहा कि बीसवीं सदी के उपनिवेशवाद से भारत ने खुद की सशक्त वैचारिकी निर्मित की। जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के बाद समाजवादी आंदोलनों की बड़ी भूमिका रही। आधुनिक भारत के निर्माण में बीसवीं सदी के दो बड़े विचारकों टैगोर और गांधी की भारतीय दृष्टि का बड़ा महत्व है।

इस सत्र में विशिष्ट वक्ता वरिष्ठ पत्रकार और रचनाधर्मी दिल्ली से अरुण कुमार त्रिपाठी ने भारतीय लोकतंत्र के आयामों पर बात की। कहा कि भारतीय लोकतंत्र की दिशा में गांधी और अंबेडकर की महती भूमिका है। भारत विरोधाभासों से बना है। इन्हीं विरोधाभासों से इसे सुदृढ़ आधार मिल रहा है। गांधी के पास फ़ौज नहीं थी, लेकिन नैतिक बल था। आज उसी नैतिकता को आगे लाने की जरूरत है। अध्यक्षीय वक्तव्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रो. पंकज कुमार ने भारतीय लोकतंत्र के सामाजिक पहलू को बताया। युवा अध्येता डॉ. जितेंद्र विसारिया और डॉ. अखिलेश पाल ने शोध वक्तव्य दिया। इस सत्र का संचालन डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया।

द्वितीय तकनीक सत्र विकास की अवधारणा और नीतियांः चुनौतियां एवं संघर्ष में कोलकाता से आए प्रो. हितेंद्र पटेल ने कहा विकास पर आने से पहले भारत की कल्पना पर आना होगा। इतिहास वृत्त को समझना होगा। राष्ट्र का निर्माण कवि कलाकार रचनात्मक लोग करते हैं। विकास 19 शताब्दी से ही परिभाषित होता रहा है। बॉम्बे प्लान का मॉडल, एमएन रॉय मॉडल, गांधीयन मॉडल। यूरोपियन मॉडल फेल होगा। एरिक हॉब्सबॉम ने कहा है कि उदारीकरण के दौर में भारत जैसे देश में जो मॉडल है उसमें मार्केट में स्वाधीनता की मांग है और राजनीति में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। विकास का जो नया मॉडल आया है, उसमें मार्केट फ्रीडम हो, लेकिन पॉलिटिक्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो। जबकि यह दोनों विरोधाभासी बातें हैं।

जीबी पंत संस्थान से डॉ. अर्चना सिंह ने कहा कि विकास की अवधारणा में स्त्रियों की उपस्थिति को समझे जाने की जरुरत है। शोध वक्तव्य देते हुए अंबेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली के एकेडमिक फेलो डॉ. रमाशंकर सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की चलती चक्की में गरीबी की गति उतनी ही तेज है, इसे रोकना होगा। राजनीतिक सिद्धांतों के शासन को समझना होगा। अजनबी किस्म की राजनीतिक और सामाजिक समझ ने भारतीय समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अध्यक्षीय वक्तव्य में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रो. आशीष सक्सेना ने विकास की सामाजिकता में निहित तत्त्वों को विस्तार से बताया। इस सत्र का संचालन राजस्थान से आए डॉ.अविचल गौतम ने किया।

तृतीय सत्र 21वीं सदी में तकनीक और गांधी में ग्वालियर से आए वरिष्ठ गांधीवादी विचारक आलोक वाजपेयी ने विविध संदर्भों में गांधी की उपस्थिति को रेखांकित किया। कहा कि गांधी सत्याग्रह को राजनीतिक यंत्र के रूप में देखते थे। कोलकाता से आए डॉ.अमित राय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आशुतोष पार्थेश्वर ने गांधी और तकनीक के रिश्ते को साहित्यिक संदर्भों और हिंद स्वराज के हवाले से परिभाषित किया। इस सत्र में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से डॉ.यशार्थ मंजुल और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन इतिहास विभाग के शोधार्थी प्रांजल बरनवाल ने शोध पत्र प्रस्तुत किया। इस सत्र की अध्यक्षता करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान की प्रो.अनुराधा कुमार ने कहा कि गांधी तकनीक के विस्तार से चिंतित थे और उनकी चिंता आज साकार रूप में दिख रही है। इस सत्र का संचालन डॉ. सुरेंद्र कुमार ने किया।

भारतीय सेना में संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार अधिसूचना जारी

प्रयागराज(नि.सं)। भारतीय सेना ने जूनियर कमीशंड अधिकारी, अन्य रैंक, अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन की घोषणा की है। संशोधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार भर्ती रैली से पहले कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) आयोजित किया जाएगा। ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकरण के लिए अधिसूचना अपलोड कर दी गई है। ''ज्वाइनइण्डियनआर्मी.एनआईसी.इन'' आवेदनों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुले हैं। उक्त जानकारी रक्षा मंत्रालय प्रयागराज के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी समीर गंगखेडकर ने देते हुए बताया है कि 16 फरवरी की शाम 5 बजे पीआईबी दिल्ली द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है। सूचना के मुताबिक उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता आवश्यकताओं (क्यूआर) के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती तीन चरणों में की जाएगी। पहले चरण में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन किया है, उन्हें कम्प्यूटर आधारित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (सीईई) से गुजरना होगा। दूसरे चरण में, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सम्बंधित सेना भर्ती कार्यालय (एआरओ) द्वारा तय किए गए स्थान पर भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण और शारीरिक मापन परीक्षण से गुजरेंगे। अंत में स्टेज थ्री में, चयनित उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट से गुजरना होगा।

संतों ने जगद्गुरु स्वामी पंचानंद गिरी के ब्रह्मलीन होने पर जताया शोक

कहा, वह सनातन धर्म के संरक्षण पर दें रहे थे जोर

प्रयागराज। जूना अखाड़ा के जगद्गुरु स्वामी पंचानंद गिरी के आज ब्रह्मलीन होने पर संत और महात्माओं में शोक की लहर है। सभी ने ब्रह्मलीन जगदगुरु स्वामी पंचानंद गिरी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह सनातन धर्म के स्तम्भ थे। उन्होंने सनातन धर्म को संरक्षण देते हुए एक नई दिशा दिया था। संत-महात्माओं ने कहा कि पंजाब में बढ़ते हुए आतंकवाद के दौरान उन्होंने आतंकवादियों से कई बार लोहा लिया था। उन पर कई बार आतंकवादियों ने जानलेवा हमला किया था। लेकिन उन्होंने आतंकवादियों का मजबूती से मुकाबला किया और उनको परास्त किया। जगदगुरु पंचानंद महराज के ब्रह्मलीन होने पर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज, अखिल भारतीय दण्डी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीठाधीश्वर स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज, किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज, उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर बोर्ड की वरिष्ठ सदस्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्या नंदगिरी, महामंडलेश्वर स्वामी राघव दास महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी रामतीर्थ दास महाराज, चित्रकूट की मानस प्रवक्ता राधिका वैष्णव, डॉ राधाचार्या सहित प्रमुख संत-महात्माओं ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि उन्होंने सनातन धर्म को सदैव संरक्षण दिया और लोगों को सनातन धर्म के मार्ग पर चलने के लिए बराबर प्रेरित करते रहे। उन्होंने देश ही नहीं विदेश में भी सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को फहराया था।

डीएम ने अटल आवासीय विद्यालय और गोशालाओं का किया निरीक्षण

कोरांव(नि.सं)।मंत्री के निर्देश के बावजूद बेलहट कोरांव में अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण में हो रही मनमानी को देख निरीक्षण करने गए जिलाधिकारी प्रयागराज संजय खत्री का पारा चढ़ गया। उन्होंने तत्काल फटकार लगाते हुए जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए।

नवंबर में श्रम मंत्री ने किया था निरीक्षण -विकास खंड कोरांव अंतर्गत बेलहट गांव में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 73 करोड़ रुपए की लागत से अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त निर्माण की गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए बीते 18 नवंबर को प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान मंत्री को कई खामियां दिखी थीं। उन्होंने चेतावनी देते हुए जांच के आदेश दिए थे। आरोप है कि बावजूद इसके ठीकेदार मनमानी करते हुए मानक के विपरीत घटिया सामग्रियों से विद्यालय भवनों का निर्माण कर रहा है। सदस्य निगरानी समिति दिशा व भाजपा के वरिष्ठ नेता तुलसीदास राणा ने भी कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कई जगह शिकायत की है।

अधिकारियों को डीएम ने लगाई फटकार -श्रमिकों के बच्चों को इंटर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के निमित्त बड़ी लागत से बनाए जा रहे अटल आवासीय विद्यालय का बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन भवनों, ,भोजनालय कक्ष,लैब,खेल के मैदान आदि का गहन पड़ताल किया। उन्होंने निर्माण सामग्रियों का भी परीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों और ठीकेदार पर जमकर भंडास निकाली। निर्माण कार्य की गुणवत्ता से नाराज डीएम ने ठीकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव को सहायक अभियंता संजीव कुमार को कारण बताओ नोटिस देने और महेश कुमार सहित तीन अन्य अवर अभियंताओं का वेतन रोकने के निर्देश दिए।उन्होंने निर्माण सामग्रियों की लैब में जांच कराए जाने का भी निर्देश दिया। इस दौरान उनके साथ उप श्रमायुक्त प्रयागराज राजेश मिश्र, डीडीओ, एसडीएम शुभम यादव, बीडीओ मुकेश कुमार सिंह,प्रभारी निरीक्षक धीरेंद्र सिंह,लेबर इंस्पेक्टर अवनीश त्रिपाठी आदि अधिकारी मौजूद रहे।गोशालाओं का भी किया निरीक्षण -आवासीय विद्यालय का निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी सीधे बेलहट और बेलवनिया की गौशालाओं का निरीक्षण करने पहुंच गए। वहां पशुओं के स्वास्थ्य और उनके भोजन को देखकर वे काफी नाराज दिखे। उन्होंने पशुओं को डाले गए पुआल की कूटी को झन्ने से छनवाकर यह देखा कि उसमें चोंकर आदि कुछ सामग्री मिलाई गई है या नहीं। गौशालाओं में गोबर का उचित प्रबंधन न किए जाने से भी वे नाराज दिखे। उन्होंने बीडीओ मुकेश कुमार सहित ग्राम प्रधान और सचिव को साफ सफाई और पशुओं के सही खानपान का निर्देश दिया।

शुआट्स में मारपीट के मामले में अतीक अहमद की याचिका खारिज

प्रयागराज(नि.सं)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुऑट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को उनके अधिवक्ता द्वारा जोर न देने के बयान पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है। लिहाजा, जमानत अर्जी खारिज की जाती है।यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अतीक अहमद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। अतीक अहमद पर शुऑट्स में मारपीट करने पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 395, 323, 504, 506 और 7 क्रिमिनल लॉ संशोधिन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कहा कि वह 11 फरवरी 2017 से लगातार जेल में हैं। इसलिए वह जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

मोटर साइकिल चोरों के गिरोह का खुलासा, चार गिरफ्तार

प्रयागराज(नि.सं)। पुलिस उपायुक्त नगर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त नगर व सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के पर्यवेक्षण में प्रभारी थाना कोतवाली व उ.नि कृष्ण कुमार सरोज अपराध शाखा पुलिस कमिश्नरेट के नेतृत्व में थाना कोतवाली व अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने आज जीआईसी स्कूल व रेलवे क्रासिंग के मध्य फ्लाई ओवर के नीचे से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से चोरी की 10 मोटर साइकिल, एक स्कूटी, एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर, 4000 रु. नकद व 6 अवैध देशी बम बरामद किया है।

मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में तरुण निषाद पुत्र अवधेश निषाद तथा अभिषेक पासी पुत्र दीपचन्द पासी नि0 उमरपुर नीवां थाना धूमनगंज, रवि पाल पुत्र ननका पाल नि0 प्रेमनगर थाना कैण्ट प्रयागराज एवं अब्दुल शेख उर्फ हुसैन पुत्र खुद्दूस शेख नि0 मालदा टाउन थाना मानिकचन्द जिला मालदा (प0बंगाल) हाल पता हड्डी गोदाम थाना करेली प्रयागराज को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि इनके द्वारा योजनाबद्ध तरीके से जनपद के अलग अलग क्षेत्रों से मोटरसाइकिल की रेकी की जाती थी। इनमें से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल खड़ी करने वाले व्यक्ति का पीछा कर रेकी करता था व अन्य दो अभियुक्तों द्वारा आस पास की रेकी की जाती थी। चौथे अभियुक्त द्वारा मोटर साइकिल चोरी की जाती थी। चोरी करने के उपरान्त इन लोगो द्वारा मोटरसाइकिलों की नम्बर प्लेट बदल दी जाती थी, जिससे चोरी की मोटर साइकिल की पहचान न हो सके।

उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मुअसं 26/23 धारा 411, 413, 414, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि, मुअसं 27/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मुअसं 28/23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, मुअसं 29/23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, मुअसं 30/23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत एनएचएआई के विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा

प्रथम चरण में चार जगहों जगतपुर, बाबूगंज, ऊंचाहार, अलापुर पर ग्रीन फील्ड बाईपास सृजित तथा सई नदी पर एक पुल का निर्माण

प्रयागराज । महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा की जा रही विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा आज एनएचएआई के अध्यक्ष संतोष यादव ने सभी सम्बंधित अधिकारियों की उपस्थिति में सर्किट हाउस में की। प्रयागराज को विभिन्न जनपदों से जोड़ने तथा यहां पर रिंग रोड के निर्माण हेतु किए जा रहे कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई।

संतोष यादव ने सर्वप्रथम प्रयागराज से रायबरेली-लखनऊ मार्ग को फोर लेन करने सम्बंधित कार्यों की जानकारी ली। जिस पर सम्बंधित प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने अवगत कराया कि इस कार्य को दो चरणों में करने का प्रस्ताव है। जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में चार जगहों (जगतपुर, बाबूगंज, ऊचाहार, अलापुर) पर ग्रीन फील्ड बाईपास सृजित किया जाएगा तथा सई नदी पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। इस चरण के सभी कार्य नवम्बर, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

द्वितीय चरण में 8.5 किमी के दो लेन को फोर लेन में उच्चीकृत करना प्रस्तावित है तथा इसका एवार्ड 31 मार्च, 2023 तक पूर्ण कर इस कार्य को मार्च 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। शेष 63 किमी हेतु निविदा आमन्त्रित की गयी है, जो मार्च 2023 तक प्राप्त कर ली जाएगी तथा 15 अप्रैल, 2023 तक कार्य एवार्ड कर दिया जाएगा। इस कार्य को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

महाकुंभ के पश्चात प्रयागराज से गोरखपुर जाने के दृष्टिगत प्रयागराज से गोरखपुर सेक्शन वाया जौनपुर आजमगढ़ को फोरलेन बनाने पर भी चर्चा हुई। सम्बंधित अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज-मुंगरा बादशाहपुर-जौनपुर- आजमगढ़-दोहरीघाट 168 किमी के 4 लेन का डीपीआर बना लिया गया है तथा दोहरीघाट से गोरखपुर चार लेन का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज से अयोध्या मार्ग, राम वन गमन मार्ग, मिर्जापुर से ड्रमंडगंज रोड तथा प्रयागराज की तहसील कोरांव में बाईपास के निर्माण सम्बंधित चर्चा भी की गई।

जनपद में प्रस्तावित रिंग रोड के बारे में चर्चा करते हुए बताया गया की कुल 65 किमी के एलाइनमेन्ट का अनुमोदन किया गया है जिसे दो चरणों में बनाया जाएगा। प्रथम चरण में सहसों से दांदूपुर तक कुल 29.5 किमी का निर्माण किया जाएगा और इसे तीन पैकेज में विभक्त किया गया है। पैकेज-1 में ग्राम दादूपुर (रीवा रोड) से ग्राम महुआरी (मिर्जापुर रोड) लम्बाई 7.6 किमी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, पैकेज-2 में ग्राम महुआरी (मिर्जापुर रोड) से ग्राम नवाबा उर्फ नीबीकला उपरहार लम्बाई 7.6 किमी का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा पैकेज-3 के अंतर्गत ग्राम नवाबा उर्फ नीबीकला उपरहार से ग्राम खुदायपुर कसगांव (एनएच-16) लम्बाई 14.763 किमी का निर्माण प्रस्तावित है।

मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सभी महत्वपूर्ण कार्यों के निरंतर अनुश्रवण हेतु मासिक रिव्यू मीटिंग करने तथा एनएचएआई एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को बेहतर समन्वय बनाते हुए सभी कार्यों का निष्पादन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री को जनपद के विभिन्न स्थानों में जहां भी भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता है, उसे शीघ्र पूर्ण कर भूमि एनएचएआई के अधिकारियों को सड़क बनाने हेतु उपलब्ध कराने को कहा।

इसी क्रम में मेला अधिकारी, कुंभ मेला विजय किरण आनंद ने कुंभ 2019 में आई भीड़ का उदाहरण देते हुए सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के सभी कार्यों को अत्यंत आवश्यक बताया तथा सभी कार्यों को अक्टूबर 2024 तक समाप्त करने का अनुरोध किया। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर, पुलिस आयुक्त रमित शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक चंद्र प्रकाश समेत सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

वर्ल्ड कैंसर दिवस के मौके पर कैंसर जागरुकता रैली का आयोजन

प्रयागराज(नि.सं)।प्रयागराज हास्पिटल एवं रोटरी क्लब ऑफ इलाहाबाद एकेडमिया के संयुक्त प्रयास से कैंसर जागरुकता रैली का आयोजन किया गया । जिसका शुभआरम्भ पदमश्री डॉ. बी. पॉल के कर कमलों द्वारा हुआ । कैंसर जागरुकता रैली में शहर के बहुत सारे चिकित्सकों के साथ शहर के प्रबुद्धजनों की भी विशेष उपस्थिति रही । इस मौके पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की लोगो को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया साथ ही प्रयागराज हास्पिटल के परिसर में एवं अटाला चौराह पर आम जनमानस के बीच डॉ. बी. पॉल (सीनियर आन्कोलॉजिस्ट) ने कैंसर के प्रति लोगों को जागरुक किया एवं इस मौके पर प्रयागराज हास्पिटल के बिदेशक डॉ. आरिफ़ क़ादरी ने बताया के कैंसर से बचाव ही कैंसर का उपचार है। इस मौके पर रोटरी क्लब एवं एकेडमिया के फाउंडर निदेशक श्री तारिक, असरा नवाज़, आफ्तान एवं इसरार अहमद के साथ सभी वार्ड के सभासद भी मौजूद रहे।

संपादकीय

बढ़ती महंगाई

महंगाई के लगातार बेलगाम बने रहने के बीच इसकी रफ्तार थामने के लिए आरबीआइ ने कई बार रेपो दरों में भी बढ़ोतरी की है। अर्थव्यवस्था के आंकड़े चाहे जितने भी बेहतर स्थिति को दर्शा रहे हों, लेकिन आम लोगों का जीवन स्तर जिन जमीनी कारकों से प्रभावित होता है, उसी के आधार पर आकलन भी सामने आते हैं। पिछले करीब तीन सालों के दौरान कुछ अप्रत्याशित झटकों से उबरने के क्रम अब अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन इसके समांतर साधारण लोगों के सामने आज भी आमदनी और क्रयशक्ति के बरक्स जरूरत की वस्तुओं की कीमतें एक चुनौती की तरह बनी हुई हैं। यों लंबे समय के बाद बीते साल दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में खासी गिरावट हुई थी और वह साल में सबसे नीचे यानी 5.72 फीसद पर चली गई थी। तब यह उम्मीद की गई थी कि अब देश शायद मुश्किल दौर से उबर रहा है और बाजार आम लोगों के लिए भी अनुकूल होने की राह पर है। लेकिन बाजार की यह गति देर तक कायम नहीं सकी। सिर्फ एक महीने बाद खुदरा मुद्रास्फीति की दर में एक बार फिर बड़ा उछाल आया है और वह पिछले तीन महीने के उच्च स्तर यानी 6.52 फीसद पर पहुंच गई है। यह चिंता की वजह इसलिए भी है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआइ ने महंगाई की दर को दो से छह फीसद के दायरे में रखने का लक्ष्य तय किया हुआ है। जनवरी से पहले लगातार दो महीने के आंकड़े खुदरा महंगाई दर में कुछ राहत देते दिख रहे थे। लेकिन अब इसका छह फीसद की सीमा को पार करना बताता है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक की ओर नीतिगत दरों में बढ़ोतरी का भी असर ज्यादा कायम नहीं रह सका। गौरतलब है कि महंगाई के लगातार बेलगाम बने रहने के बीच इसकी रफ्तार थामने के लिए आरबीआइ ने कई बार रेपो दरों में भी बढ़ोतरी की है। इसका तात्कालिक असर भी पड़ता दिखा। लेकिन बाजार में जरूरी वस्तुओं की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है और खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 5.94 फीसद पर जा पहुंची है। हालांकि सब्जियों के दाम फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन दूध, मसालों के अलावा ईंधन और प्रकाश वर्ग में कीमतों के इजाफे ने फिर मुश्किल पैदा की है।यह स्थिति इसलिए भी खतरे की घंटी है कि आरबीआइ इस समस्या के संदर्भ में फिर रेपो दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। यह अलग सवाल है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपनाई गई मौद्रिक नीतियां किस स्तर तक कामयाब हो पाती हैं। जाहिर है, बाजार में खाने-पीने और रोजमर्रा की अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ने न केवल आम जनता, बल्कि सरकार के माथे पर भी शिकन पैदा की है। वजह यह है कि महंगाई से परेशान लोगों ने लंबे समय से इसकी मार झेलते हुए इसकी वजहों को समझने की कोशिश की और संयम बनाए रखा।

समानता और समावेशी विकास के रास्ते

-अखिलेश आर्येंदु

कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में गैरबराबरी बढ़ाने वाले कार्य किए। नतीजतन, गांवों से शहर की ओर पलायन हुआ और शहर सुरसा की तरह बढ़ते गए। तमाम महानगरों के आसपास नए उपनगर उगते जा रहे हैं। इन शहरों में एक-डेढ़ दशकों में ही नए धनपतियों का उदय हुआ जो देखते-देखते भारत के सौ प्रमुख धनपतियों में शामिल हो गए। लेकिन सरकारों ने कभी यह समझने की कोशिश नहीं की कि कुछ वर्षों में ही इनके पास इतनी संपत्ति कहां से इकट्ठा हो गई! केंद्र के नए बजट को आमतौर पर किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए कई नजरिए से बेहतर कहा जा रहा है। माना जा रहा है कृषि नवाचार यानी स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, वे मील के पत्थर साबित होंगे। बजट में बीस लाख करोड़ से 'एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड' यानी कृषि त्वरक कोष बनाने की घोषणा के साथ बेहतर तकनीक मुहैया कराने और भूमि रिकार्ड के डिजिटलीकरण और खेती में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। कृषि ऋण में ग्यारह फीसद का इजाफा करते हुए इसे बीस लाख करोड़ किया गया है। मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन के लिए छह हजार करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू करने की बात भी कही गई है। वहीं महिला किसानों के लिए चौवन हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, तो सैंतालीस लाख युवाओं को तीन साल तक भत्ता देने की बात भी की गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा बढ़ाकर तीस लाख रुपए किया गया है। यानी इस बजट के जरिए समाज के हर वर्ग को साधने और खुश करने की कोशिश की गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए बजट बढ़ा है या यह आंकड़ों की जादूगरी है, जैसा कि विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें विकास की जिस रफ्तार की बात करती हैं, क्या वाकई विकास की यही हकीकत है या आंकड़े और हकीकत में अंतर है दरअसल, केंद्र सरकार जिस हकीकत को संसद के सदनों में और जनता के सामने बयां करती है, वे सरकारी आंकड़े हैं। रिजर्व बैंक की 31 अक्तूबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में उस वक्त तक कुल कर्ज 128 लाख करोड़ रुपए था जो 31 मार्च 2022 को जारी दूसरी रिपोर्ट में बढ़कर 133 लाख करोड़ हो गया। यानी महज तीन महीने में देश पर पांच लाख करोड़ का कर्ज और बढ़ गया। अब हालत यह है कि देश पर 142 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। रुपए के मुकाबले बढ़ते डालर के दाम से कर्ज का यह बोझ लगातार बढ़ रहा है। गौरतलब है पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे-खाते में डाल दिए गए। अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात इस बढ़ते कर्ज की वजह से हकीकत से बहुत दूर है। इससे गैरबराबरी में इजाफा हुआ है। मुल्क में जहां अमीरों की तादाद तेजी से बढ़ी है, वहीं गरीब भी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। सवाल यह है कि वैश्वीकरण के बाद शहरीकरण की बढ़ती रफ्तार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अर्थव्यवस्था में बढ़ते एकाधिकार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने क्या कोई कदम उठाए हैं आजादी के बाद से ही केंद्र और राज्य सरकारें ऐसा कदम नहीं उठाती आई हैं, जिससे किसान-मजदूरों की बदहाली में आमूलचूल बदलाव आए। अब केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पुराने ढर्रे को छोड़ कुछ नया करने जा रही है। इसमें कृषि को अधिक उदारवादी नीति के अंतर्गत लाना शामिल है। लेकिन जिस उदारवादी नीति पर केंद्र सरकार चल रही है, उससे किसानों और मजदूरों का न शोषण रुका है और न उनकी आत्महत्याएं। आशंका इस बात की जताई जाती है कि आने वाले वक्त में खेती भी कहीं धनपतियों के अधिकार क्षेत्र में न आ जाए और किसान अपनी जमीन का नाममात्र का मालिक बन कर रह जाए। भारतीय शहरों में पश्चिमी देशों की तरह के बड़े-बड़े व्यावसायिक परिसर, मल्टीप्लेक्स, पांचसितारा होटल और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ऊंची इमारतें देश की किस तरह की तस्वीर पेश कर रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यह आश्वासन दिया जा रहा है कि देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खरीदकर खुद ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई हैं। विश्व के धनपतियों की सूची में भारतीय मूल के उद्योगपति भी काफी ऊपर हैं। सतह पर दिखाई जाने वाली तस्वीर से लगता ही नहीं कि देश में अब भी करोड़ों की तादाद में बेराजगार, भुखमरी के शिकार गरीब, कर्जदार किसान, मजलूम और जरूरी मेडिकल मदद के अभाव में दम तोड़ते गरीब भारतीय भी हैं। जो तस्वीर सार्वजनिक रूप से पेश की जा रही हैं, उससे लगता है कि वे दिन दूर नहीं, जब देश का हर आदमी खुशहाल और साधन संपन्न होगा और रोजमर्रा की तमाम बदहाल करने वाली समस्याओं से पार पा चुका होगा। इस तस्वीर की उम्मीद किसी को भी होगी। 'क्रेडिट सुइस ग्रूप एजी' के मुताबिक देश की आधी आबादी के पास महज 2.1 फीसद संपत्ति है। आंकड़े के मुताबिक 2010 में देश के एक फीसद लोगों की संपत्ति चालीस फीसद थी जो 2016 में बढ़कर 58.4 फीसद हो गई। इसी तरह 2010 में 10 फीसद लोगों के पास देश की 68.8 फीसदी संपत्ति थी, लेकिन 2016 में बढ़कर 80.7 फीसदी संपत्ति पर उनका कब्जा हो गया।इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि पिछले चार वर्षों में गरीबों की अतिरिक्त दस फीसद संपत्ति छिन गई। इसे छीनने का काम देश-दुनिया के शीर्ष धन्नासेठों की कंपनियों ने किया और बड़ी होशियारी से इसका नाम 'विकास के नए आयाम' देकर लोगों को ठगा गया। भारत के महज एक फीसद लोगों के पास ही सबसे अधिक संपत्ति है। यहां दुनिया के करोड़पतियों में से पांच फीसद करोड़पति और दो फीसद अरबपति रहते हैं।इसी तरह मुंबई में सबसे अधिक 1,340 धनपति रहते हैं। 'नाइट फ्रैंक वेल्थ' की रपट के मुताबिक अगर यही रफ्तार जारी रही तो महज दो वर्षों में दस हजार से अधिक नए धनपति इस कतार में जुड़ जाएंगे। जाहिर है, जैसे-जैसे गैरबराबरी बढ़ रही है, वैसे-वैसे गरीबों और अमीरों की तादाद बढ़ती जा रही है।

'मानव-मंदिरों' को तोड़ने के बढ़ते प्रचलन से जुड़े सवाल मांग रहे दो टूक जवाब

-कमलेश पांडे

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा महरौली में चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान उन मकानों को भी तोड़ डाला गया, जिसकी रजिस्ट्री उनके भूस्वामियों या फ्लैट मालिकों के पास मौजूद है। बिजली, पानी, गैस के बिल के साथ-साथ सभी वैध पहचान पत्र भी उनके पास हैं। अपने आशियाना को बचाने के लिए जब वो सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, तो उनके वेश-भूषा से प्रतीत हो रहा था कि सभी लोग निम्न मध्यम वर्गीय या मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। फिर भी उन्हें इस प्रशासनिक अनहोनी का सामना करना पड़ा। अब वो लोग घर से ऐसे बेघर कर दिए गए जैसे कि यहां के निवासी ही नहीं हों और उनके प्रति शासन-प्रशासन का कोई नैतिक दायित्व भी नहीं बनता है। सच कहूं तो यह अतिक्रमण विरोधी अभियान महज एक बानगी भर है। जबकि ऐसे कई अभियान दिल्ली-एनसीआर समेत देश के किसी न किसी हिस्से में आये दिन चलते ही रहते हैं, जिससे कभी नियम-कानून तो कभी मानवता और कभी-कभी तो दोनों तार-तार होते दिखाई-सुनाई पड़ते हैं। ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियानों के शिकार प्रायः सभी लोग भारतीय होते हैं, लेकिन इनके खिलाफ भारतीय अधिकारियों का व्यवहार गैर-जिम्मेदाराना दिखाई देता और सुनाई पड़ता है। सवाल है कि आखिर यह सब कब तक चलता रहेगा। उससे भी बड़ा सवाल यह कि आखिरकार ऐसे अतिक्रमण विरोधी अभियान ब्रेक के बाद क्यों चलाये जाते हैं, क्यों नहीं पूरे देश में एक साथ चलाये जाते हैं। वहीं, जिन अतिक्रमणों से सरकारी अधिकारी जानबूझकर मुंह फेर लेते हैं, उनके खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान कौन चलाएगा। अनुभव बताता है कि जब तक लोग बाग विकास प्राधिकरण के लोगों, नगर निगम के लोगों, जिला प्रशासन या अनुमंडल प्रशासन के लोगों के इशारे पर उलटफेर करते रहते हैं, तबतक कोई भी अतिक्रमण जायज होता है। लेकिन जैसे ही उस उलटफेर पर सवाल उठने लगते हैं, वह नाजायज हो जाता है और ध्वस्त कर दिया जाता है। नई नवेली अवैध कॉलोनियों, शहरी पार्कों या ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर ऐसे अतिक्रमण आम बात बन चुके हैं और उनपर कार्रवाई भी मुंह देखकर की जाती है। पीडब्ल्यूडी की सड़कों व राजमार्गों व रेल की परिसम्पत्तियों से जुड़े अतिक्रमण का भी यही हाल है। रक्षा मंत्रालय या अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार के विभागों की अनुपयोगी भूमि की बंदरबांट भी कुछ इसी प्रकार होती आई है। इसलिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला सरकार को ऐसे अतिक्रमणों पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, अन्यथा पीक एन्ड चूज वाली कार्रवाई बन्द करनी चाहिए। दरअसल, जिस घर में लोग रहते हैं, उसे मैं 'मानव मंदिर' समझता हूँ, क्योंकि गृह स्वामी और गृह स्वामिनी अपने उसी घर से न केवल अपने बुजुर्गों और बच्चों की परवरिश करते हैं, बल्कि मानव समाज और प्राणी समाज के काम भी वक्त बेवक्त आते रहते हैं। ऐसे ही लोगों से मिलकर यह देश-समाज बनता है। ऐसे में जब उनमें से कुछ घरों यानी झोपड़ियों से लेकर मकानों तक पर बुलडोजर चलते हैं और वैसे ही 'अतिक्रमित देव मन्दिर' छोड़ दिये जाते हैं, तो ऐसी दोमुंही विधि-व्यवस्था पर कुछ सवाल उठने लाजिमी हैं। कहा भी गया है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, वो तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये चंद पक्तियां भले ही सामाजिक या सांप्रदायिक उन्मादियों को लक्षित करके लिखी गईं हों, लेकिन भारतीय संवैधानिक सत्ता को अपने मन के मुताबिक हांकने वाले प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों, जिनके 'गुप्त गठजोड़' राजनेताओं-पूंजीपतियों तक से रहते आये हैं, पर भी बड़ी सटीक बैठती हैं! क्योंकि 'हम भारत के लोग' के खिलाफ इनका 'पीक एन्ड चूज' वाला जो रवैया है, वह भारतीय संवैधानिक व्यवस्था से 'बलात्कार' नहीं है तो क्या है सुलगता सवाल है कि यदि यह संवैधानिक तंत्र समाज के अंतिम आदमी व उसके परिजनों के आंख की आंसू जब पोंछ नहीं सकता, तो उसे अपने 'अवांछित कृत्यों' से उन्हें रूलाने का भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन यह आजादी के अमृतकाल में भी बदस्तूर जारी है! देखा जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों से अतिक्रमण विरोधी अभियान का जो क्रूर चेहरा सामने वक्त-बेवक्त आया है, वह ब्रितानी शासकों के अत्याचारों को भी पीछे छोड़ चुका है। मेरा विचार है कि किसी को भी कहीं से उजाड़ने के पहले उसके पुनर्वास की उचित व्यवस्था करना भारतीय प्रशासन का दायित्व है, जिसके निर्वहन में वो कई बार विफल दिखाई देती है। ऐसे मामलों में न्यायालय द्वारा भी स्वतः संज्ञान न लिया जाना लोगों के दुःख-दर्द को बढ़ाने वाला साबित होता है, क्योंकि खर्चीली, दीर्घसूत्री और अपराधियों के बच निकलने वाले तमाम कानूनी छिद्रों के चलते हर कोई भारतीय न्याय व्यवस्था के दरवाजे खटखटाने से पहले सौ बार सोचता है। इसलिए भारतीयों के बीच से बने नौकरशाहों व न्यायविदों से यह अपेक्षा की जाती है कि संविधान प्रदत्त विवेक के अनुप्रयोग के अधिकारों का बेजा इश्तेमाल किसी को फंसाने या बचाने के वास्ते नहीं करें, बल्कि सिस्टम से किसी न किसी तरह से पीड़ित हुए लोगों को वाजिब न्याय दिलाने के लिए करें। क्योंकि एक की तरफदारी करते हुए दूसरों को न्याय न देने की कोशिश एक ऐसी विकृत मानसिकता है जो देश व समाज को किसी गलत संस्कृति की तरफ धकेल रही है। अतिक्रमण विरोधी अभियानों से जो बातें क्षणकर सामने आ रही हैं, वो यह कि जिन मकानों की रजिस्ट्री हुई है, उन्हें भी तोड़ दिया जाता है। क्या यह रजिस्ट्री तंत्र की विफलता नहीं है यदि हाँ, तो फिर आम आदमी उसे क्यों झेले। सवाल है कि भारत में कानूनी साक्षरता दर बहुत कम है। अधिकांश लोग रजिस्ट्री हुई संपत्ति या बैंक लोन पास होने वाली सम्पत्ति को सही मानते हैं। जब स्थानीय भू-राजस्व कार्यालय ही भूमि माफियाओं से मिलकर इफ एन्ड बट की बात करे तो आमलोगों का उलझना लाजिमी है। अधिकांश भूमि अतिक्रमण मामलों में कुछ ऐसे ही खेल हुए हैं। इसमें जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी बच जाते हैं और आम आदमी तबाह हो जाता है। आखिर जब राशन कार्ड, बिजली बिल, पानी बिल, गैस बिल, मतदाता पहचान पत्र आदि वैध दस्तावेज समझे जाते हैं, तो फिर इसके धारक सम्बन्धित भूमि पर अवैध कब्जाधारी कैसे हो गए, प्रशासन खुद आत्मचिंतन, आत्ममंथन करे। इसलिए यदि किसी भी सरकारी या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है और अतिक्रमणकारी वहां वर्षों से काबिज हैं और संपत्ति स्वामी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वर्षों से शिकायत नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे जगहों पर वर्षों से बसे लोगों को अचानक उजाड़ देना और उनके समुचित पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करना लोगों पर अकस्मात थोपित प्रशासनिक आपदा नहीं है तो क्या है मानवता के इस हनन को मानवतावादी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार से अपेक्षा है कि वह पूरे देश में अतिक्रमण सम्बन्धी एक श्वेत पत्र जारी करे और एक डेटलाइन तय करे कि इसके बाद अतिक्रमित हुई सरकारी सम्पत्तियों पर चरणबद्ध रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सरकार यह भी स्पष्ट करे कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही या फिर भूमाफियाओं से उनकी परोक्ष सांठगांठ के चलते जिन सरकारी जमीन की रजिस्ट्री किसी व्यक्तिविशेष के नाम हुई है तो वह ऐसा करने वाले गिरोह के खिलाफ क्या कार्रवाई की है, कर रही है और उस गिरोह की कारगुजारियों का शिकार हुए व्यक्ति को क्या क्षतिपूर्ति दे सकती है। क्योंकि जब प्रशासनिक तंत्र विफल या विद्वेषी हो जाता है, तभी समाज में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला बढ़ जाता है। जिसकी कीमत आम आदमी को कभी न कभी चुकानी पड़ती है, लेकिन वह कब तक चुकाएगा, यह यक्ष प्रश्न है। इसके अलावा, वह यह भी स्पष्ट करे कि यदि सरकारी भूमि पर 'मानव मन्दिर' जायज नहीं है तो फिर वैसी ही भूमि पर बने 'धार्मिक मन्दिर' जायज कैसे हो सकते हैं और सरकारी तंत्र ऐसे धर्मस्थलों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और कबतक कर सकता है।

दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं ये गलतियां

सफेद चमकते दांत हर किसी का सपना होते हैं। लोग इन्हें सुंदर बनाने और दिखाने के लिए कई जतन भी करते हैं। दिन में दो बार ब्रश करना, माउथ वॉश आदि का इस्तेमाल करने के बावजूद जाने-अनजाने में छोटी-बड़ी गलतियां कर जाते हैं। खास बात यह है कि इन गलतियों की आदत हो जाती है और यह पता नहीं होता है कि वास्तव में ये आदतें नुकसान पहुंचा रही हैं। दांतों में मैल, कैविटी और दांत का दर्द इन गलतियों का ही परिणाम होता है। डॉ. राज़ी अहसान का कहना है कि कैविटी यानी दांतों का सड़ना या कीड़े लगना तब होता है जब कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना जैसे ब्रेड, अनाज, दूध, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फल, केक या टॉफी दांतों में रह जाते हैं। इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया इसे एसिड में बदल देते हैं। बैक्टीरिया, एसिड, दांतों में अटका खाना और लार मिलकर प्लाक बनाता है, जो दांतों से चिपक जाता है। प्लाक में मिला एसिड इनेमल को खत्म कर देता है और छेद कर देता है। यह कैविटी समय के साथ बड़ी भी हो जाती है।

एम्स की डॉ. वीके राजलक्ष्मी का कहना है कि दांतों में मैल जमने का खतरा तब बढ़ जाता है जब बार-बार खाना खाते हैं। ओरल हाइजिन खराब होती है या फिर लोग सिगरेट या तंबाकू खाते हैं। रोजमर्रा की कई ऐसी आदतें है, जिनसे दांतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और दांतों में ये सब परेशानियां पैदा होने लगती है।

सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करने के बाद ही खाना और पीना ठीक है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि दिन का आखिरी काम ब्रश करना ही होना चाहिए, क्योंकि सोने से पहले चाय पीना भी दांतों पर गलत प्रभाव डालता है।रोजाना दांतों को केवल 30 सेकंड तक ब्रश करने से कोई अच्छे नतीजे नहीं मिलने वाले है। इससे कैविटी और दांतों की अन्य समस्या हो सकती है। चारों कोनों में कम से कम 30 सेकंड देना चाहिए यानी पूरे मुंह के लिए 2 मिनट का समय देना चाहिए।दांतों की सफाई की बात आती है तो कई लोग बहुत कठोर तरीके से ब्रश करते हैं। लेकिन ऐसा करने से इनेमल को नुकसान पहुंचता है और दांत संवेदनशील हो जाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि टूथब्रथ व्यक्ति को सूट करता हो।

इतना ही नहीं खाना खाने के तुरंत बाद भी ब्रश करना इनेमल पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, विशेष रूप से जब कुछ एडिसिक खाया हो। इसलिए खाना खाने के 30 मिनट तक ब्रश नहीं करना चाहिए।

शोधकर्ताओं के मुताबिक हर तीन महीने में ब्रश बदलना चाहिए। ऐसा न करने पर दांतों के क्षय की संभावना रहती है, क्योंकि टूथब्रश के ब्रिसल्स खराब हो जाते है और यह दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं।

टूथब्रथ मुंह में बैक्टीरिया को नहीं मार सकता है। जब कोई बीमार हो तो ब्रश बदल लेना चाहिए, ताकि दूसरी बार बीमारी फिर न पकड़ ले। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उस दौरान अन्य टूथब्रश उसके संपर्क में न आएं, जब व्यक्ति बीमार हो। मुंह से आने वाली बदबू खराब हाइजिन या गम डिसीज की ओर इशारा करती है।

ध्यान लगाने से बच्चों में कम होगा मोटापा

माइंडफुलनेस (ध्यान लगाना) आधारित थेरेपी का इस्तेमाल करने से बच्चों में तनाव, भूख और वजन को कम करने में मदद मिलेगी। एक हालिया शोध में यह खुलासा किया गया है। मोटापे और घबराहट से जूझ रहे बच्चों को ध्यान लगाने से फायदा हो सकता है।

क्या है माइंडफुलनेस : माइंडफुलनेस एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें ध्यान लगाने की क्रिया का उपयोग कर निजी जागरुकता को बढ़ाने और बीमारियों से संबंधित तनाव को दूर करने के लिए किया जाता है। ऐसे में दोनों आहार और माइंडफुलनेस का इलाज का इस्तेमाल कर मोटे बच्चों में वजन कम करने की प्रक्रिया को बेहतर किया जा सकता है।

ऐसे किया गया शोध : पत्रिका इंडोक्राइन कनेक्शन में प्रकाशित शोध में पाया गया कि मोटापे से पीड़ित जिन बच्चों को कम कैलोरी वाले आहार के साथ माइंडफुलनेस की थेरेपी दी गई उनका वजन, भूख और तनाव उन बच्चों से ज्यादा घटा जो सिर्फ कम कैलोरी वाला आहार ले रहे थे। शोध के निष्कर्षों से यह पता चलता है कि माइंडफुलनेस में इतनी क्षमता है कि मोटे बच्चों को न सिर्फ वजन कम करने में मदद मिलेगी बल्कि उन्हें उच्च रक्तचाप और मस्तिष्काघात के जोखिम से भी निजात मिलेगी। पूर्व के कई शोधों में दर्शाया गया कि तनाव और ज्यादा खाने के बीच मजबूत संबंध है। इस शोध में शोधकर्ता मारडिया लोपेज ने माइंडफुलनेस आधारित थेरेपी का तनाव, भूख और वजन पर प्रभाव देखा। उन्होंने कहा, हमारे शोध से पता चला है कि सीमित आहार लेने से बच्चों की घबराहट और चिंता में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन सीमित आहार के साथ माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से तनाव और वजन कम करने में मदद मिलेगी।

कई बीमारियों की वजह बन सकता है वजन-बचपन में होने वाला मोटापा कई बीमारियों जैसे दिल संबंधी बीमारियां और मधुमेह की वजह बन सकता है। इसके अलावा बच्चों में तनाव और घबराहट की समस्या भी पनपती है। माइंडफुलनेस का तनाव और वजन से इतना मजबूत संबंध होने के बाद भी ज्यादातर इलाज में मनोवैज्ञानिकों कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

यूरिन इन्फेक्शन से बचना है तो बरतें ये सावधानियां, अपनायें घरेलू उपाय

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन (यूटीआई) एक आम समस्या है जो महिलाओं और पुरुषों में सामान्य रूप से होती है। यह इन्फेक्शन (संक्रमण) तब होता है जब मूत्राशय और इसकी नली बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है। स्त्रीरोग विशेषज्ञ से जुड़े लक्ष्मीदत्ता शुक्ला के अनुसार, यूरिन इन्फेक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे शरीर की सफाई का ध्यान रखे बगैर शारीरिक संबंध बनाने के कारण, लंबे समय तक पेशाब रोके रखना, डायबिटीज, गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के समय इन्फेक्शन आदि। यूरिन इन्फेक्शन के लक्षणों में शामिल हैं - बार-बार पेशाब आना, पेशाब कम आना, पेशाब करते समय जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बुखार और उल्टी की शिकायत होना।

यूरिन इन्फेक्शन रोकने के घरेलू उपाय

आंवला और धनिया यूरिन इन्फेक्शन के सबसे कारगर इलाज बताए गए हैं। आयुर्वेद के मुताबिक, 50 ग्राम आंवले के रस में 30 ग्राम शहद मिलाकर दिन में तीन बार सेवन करें। ऐसा 7 दिन तक करने से पेशाब खुलकर आती है और जलन शांत होती है। इसी तरह 15 ग्राम धनिया को रात में पानी में भिगोएं। सुबह इसे ठंडाई की तरह पीसकर छान लें। फिर उसमें मिश्री मिलाकर पिएं। इससे पेशाब की जलन शांत होगी और यूरिन भी ठीक से पास होगा। इन दोनों चीजों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे- धनिया और आंवले का चूर्ण समान मात्रा में मिलाकर रात

को भिगोकर रख दें। सुबह इसे छान लें। इस पानी को पीने से यूरिन इन्फेक्शन में राहत मिलती है। इसी तर्ज पर गेहूं का उपयोग किया जा सकता है। गेहूं के 10-15 दाने रात को एक ग्लास पानी में भिगो दें। सुबह उसे छान लें और उसी पानी में करीब 25 ग्राम चीनी मिलाकर पिएं। इससे यूरिन करते समय जलन नहीं होगी और पेट भी शांत रहेगा।

इलायची की तासीर भी ठंडी है और यह यूरिन इन्फेक्शन में तत्काल राहत दिलाती है। आयुर्वेद के मुताबिक, 2 ग्राम इलायची का पाउडर समान मात्रा में दूध और पानी के साथ उबालें। अच्छी तरह उबाल आने के बाद दूध को ठंडा कर लें। इसमें चीनी मिलाएं और आधे-आधे घंटे के अंतराल पर पिएं। इलायची का उपयोग सोंठ के साथ भी किया जाता है। समान मात्रा में इलायची और सोंठ का पाउडर लें। इसको अनार के रस या दही में मिलाएं। स्वाद बढ़ाने के लिए नमक मिलाएं और सेवन करें। यूरिन इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। एक और तरीका है नारियल पानी का। नारियल पानी में गुड़ और धनिया पावडर मिलाकर पीने से यूरिन इन्फेक्शन में आराम मिलता है। इसी तरह प्याज को बारीक काटकर पानी में उबालें। इस पानी को ठंडा करने के बाद सेवन करें। इनके अलावा सेब का सिरका, बेकिंग सोडा, अनानास और ब्लूबेरी का सेवन फायदेमंद है।

इन बातों का रखें ध्यान, यूरिन इन्फेक्शन से रहेंगे दूर

यूरिन इन्फेक्शन का खतरा महिलाओं में अधिक होता है। इससे बचने के लिए जरूरी है साफ सफाई। अपने शरीर के साथ ही साफ टॉयलेट का ही इस्तेमाल करें। इससे संक्रमण नहीं होगा। यदि यूरिन इन्फेक्शन का संकेत मिल रहा है तो गर्म पानी पीना शूरू करें। इससे तेज पेशाब आएगा और संक्रमण दूर हो जाएगा।

बाइकिंग करती हैं तो इस तरह रखें अपनी त्वचा और बालों का ध्यान

सान के तरह-तरह के शौक होते हैं, जिनमें से एक है बाइकिंग। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें बाइकिंग या बाइक की सवारी बहुत पसंद है, लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि इस दौरान धूप के साथ सीधे तौर पर काफी लंबे समय तक संपर्क में रहना पड़ता है, जिससे बाल और त्वचा प्रभावित होती है। सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचने का सबसे आसान उपाय घर से बाहर निकलते समय हाथों और त्वचा को अच्छे से ढंक लेना है। हालांकि यह पयार्प्त नहीं है। बालों और त्वचा की सही देखभाल के लिए हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बाइक की सवारी करते हैं तो इन टिप्स को आजमाकर आप अपनी स्किन और बालों की देखभाल कर सकते हैं।

स्किन केयर टिप्स :

गर्मियों के मौसम में त्वचा पर इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों का प्रभाव काफी ज्यादा होता है जो त्वचा की उत्तकों को क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जिसके चलते पिगमेंटेशन की समस्या पैदा हो जाती है। इनसे बचने के लिए सबसे जरूरी यह है कि आप अपनी त्वचा का ख्याल रखें। सफर करते वक्त एसपीएफ क्रीम लगाना न भूलें। इससे सूरज की किरणों के हानिकारक प्रभावों से बचने में मदद मिलती है और पिगमेंटेशन के होने का खतरा भी टल जाता है।

बाइक पर लंबे समय तक सफर करने से त्वचा में नर्मी कम हो जाती है और यह बेजान दिखने लगता है, तो इसमें दोबारा जान डालने के लिए अपने चेहरे को किसी अच्छे क्लीनजर से साफ करें। इसके बाद टोनर का इस्तेमाल करें और आखिर में एक हाइड्रेटिंग माइश्चराइजर के साथ त्वचा को माइश्चराइज करना न भूलें। क्लीनिंजिंग, टोनिंग और माइश्चराइज स्किन केयर का एक अहम हिस्सा है। हमेशा अपनी त्वचा के हिसाब से ही उत्पादों का चुनाव करें।

बाइक पर सफर करने के दौरान हमारी त्वचा धूप और प्रदूषण के संपर्क में भी आती है और अगर आपकी त्वचा ऑइली है, तो इससे बहुत नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे में अपने साथ हमेशा वेट वाइप्स रखें।

सफर के दौरान अपने होंठों को भी अनदेखा न करें, उनका भी पयार्प्त ख्याल रखें। किसी अच्छे लिप बाम या लिप हाइड्रेटर का हमेशा इस्तेमाल करें।

इन सबके साथ एक और बात पर गौर फरमाना जरूरी है और वह ये कि लंबे रोड ट्रिप पर जाने के दौरान चेहरे पर अधिक मेकअप अप्लाई न करें। त्वचा का सांस लेना जरूरी है, मेकअप से ऐसा नहीं हो पाता है। चाहें तो सिंपल आईलाइनर और लिपस्टिक जरूर लगा सकते हैं।

हेयर केयर टिप्स :

सफर के दौरान बालों को हमेशा अच्छे से बांध लें। हेयर स्कार्फ का भी इस्तेमाल करें, इनसे बाल नहीं उलझते हैं। रोड ट्रिप पर हेयर स्प्रे न लगाएं, इससे धूल बालों में आसानी से चिपक जाती है।

हाथ से खाना खाएंगे तो बढ़ जाएगा भोजन का स्वाद

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर लोग खाना खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल करते हैं। जबकि, हाथ से खाना खाने के कई फायदे होते हैं। एक हालिया अध्ययन के मुताबिक, हाथ से भोजन करने पर भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। लेकिन, साथ ही अध्ययन का यह भी कहना है कि इससे वजन बढ़ने की संभावना भी रहती है, क्योंकि हाथ से खाना ज्यादा खाया जाता है। यह अध्ययन रिटेलिंग नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है।

दिमाग की संवेदी तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं :

वैज्ञानिकों के मुताबिक, जब खाने को हाथ से खाया जाता है तो उससे दिमाग की संवेदी तंत्रिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और भोजन के प्रति हमें सुकून का अहसास कराती हैं।

पनीर के टुकड़ों पर किया गया शोध

इस शोध के अंतर्गत वै?ज्ञानिकों ने कुछ लोगों को पनीर के टुकड़े हाथ से खाने को कहा और कुछ को चम्मच से। बाद में जो निष्कर्ष निकलकर आया। उसके अनुसार जिन लोगों ने पनीर हाथ से खाया उन्हें यह ज्यादा स्वदिष्ट लगा।

स्वाद ही नहीं वजन भी बढ़ाती है आपकी ये आदत-

रिटेलिंग नामक जर्नल में प्रकाशित हुए अध्ययन के अनुसार कहा गया है कि हाथ से खाना खाने से वजन बढ़ने की भी संभावना बनी रहती है, क्योंकि हाथ से खाना ज्यादा खाया जाता है।

इमरान खान को जाना पड़ेगा जेल, अंतरिम जमानत खारिज

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। इस्लामाबाद में एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के तोशखाना मामले में अपने फैसले के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन से संबंधित एक मामले में अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के अनुरोध को खारिज कर दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, खान के बार-बार अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास हसन ने फैसला सुनाया।इससे पहले, अदालत ने खान को दोपहर 1:30 बजे तक पेश होने का निर्देश दिया था और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। इस्लामाबाद मार्च के दौरान वजीराबाद में हत्या के प्रयास में घायल होने के बाद से इमरान खान अपने लाहौर स्थित आवास पर आराम कर रहे हैं। खान के वकील ने अदालत से यह तर्क देते हुए जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया कि पूर्व प्रधानमंत्री ने पेश होने की कोशिश की थी लेकिन यात्रा नहीं कर सके। अदालत ने कहा कि खान को उसके सामने पेश होने के लिए कई मौके

दिए गए 'लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।' जज ने याद दिलाया कि पाकिस्तान तेजरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख 31 अक्टूबर, 21 नवंबर, 28 नवंबर, 9 दिसंबर, 19 दिसंबर, 10 जनवरी, 31 जनवरी, 10 फरवरी और आज दो बार अदालत में पेश नहीं हुए।अदालत ने कहा कि तत्काल जमानत आवेदन की लंबी प्रकृति के कारण, मामले को अनिश्चित काल के लिए नहीं खींचा जा सकता है, इस प्रकार व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांगने का कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा। हालांकि, पूर्व प्रधानमंत्री गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में आदेश को चुनौती दे सकते हैं। डॉन के अनुसार, फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।

कीटनाशकों के छिड़काव तक ही सीमित नहीं है ड्रोन : सरकार

इंदौर। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि कृषि क्षेत्र में ड्रोन की उपयोगिता कीटनाशकों के छिड़काव से कहीं आगे की है तथा जैविक एवं प्राकृतिक खेती में भी इसका इस्तेमाल किये जाने की जबर्दस्त गुंजाइश है। भारत में ड्रोन उद्योग पिछले डेढ़ साल में 6-8 गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि भारत का उद्देश्य वर्ष 2030 तक ड्रोन के लिए एक वैश्विक केंद्र बनना है, जिसके लिए 'उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना' (पीएलआई) सहित एक उद्योग अनुकूल नीति लागू है।यहां जी-20 के कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक के इतर मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''ड्रोन को संकीर्ण दृष्टि से न देखें। सेवा के रूप में ड्रोन उपयोग की बहुमुखी क्षमता और विविधता कहीं अधिक है।'' कृषि में ड्रोन का उपयोग केवल कीटनाशकों के छिड़काव तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका इस्तेमाल भूमि के नक्शे को डिजिटल रूप देने और कृषि भूमि के सर्वेक्षण में किया जा सकता है। सिंधिया ने कहा, ''जैविक खेती के लिए ड्रोन का उपयोग भी जबर्दस्त तरीके से हो सकता है। यहां तक कि प्राकृतिक खेती में भी ड्रोन के उपयोग की जबर्दस्त गुंजाइश है।'' सरकार रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और जमीन के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश वर्तमान में जैविक खेती में अग्रणी है। मौजूदा समय में खेती में ड्रोन उपयोग की अनुमति केवल कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ही है। भविष्य में कई और उपयोगों के सामने आने की बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ड्रोन के कई इस्तेमाल हैं।

तुर्किए में संचार प्रणाली के जरिए भारत कर रहा मदद

नई दिल्ली (वेब वार्ता)।भूकंप से प्रभावित तुर्किए में भारतीय सेना और NDRF की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय सेना भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाने के साथ-साथ अन्य तरीकों

से भी मदद का समाधान ढूंढ़ने में लगी हुई है। इसी क्रम में कैप्टन करण सिंह और सब पीजी सप्रे सहित सेना की एक टीम ने एक नेटवर्क-स्वतंत्र, रीयल टाइम ट्रैकिंग और मैसेजिंग मॉड्यूल- 'संचार' विकसित किया है, जिसका उपयोग सभी रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपनी टीम के सदस्यों और संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब इसी संचार प्रणाली का उपयोग तुर्किये में उन क्षेत्रों में भी किया जा रहा है जहां स्थानीय आबादी को राहत देने के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। भारत की तरफ से 10 फरवरी को तुर्किए और सीरिया दोनों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री की व्यवस्था की गई थी। सीरिया के लिए भेजी गई खेप में 7.3 टन की 72 महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, उपभोग्य वस्तुएं और सुरक्षात्मक वस्तुएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपये है, जबकि तुर्किए के लिए भेजी गई राहत सामग्री में 14 प्रकार के चिकित्सा और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपये है। बता दें कि छह फरवरी को तुर्किए और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के एक हफ्ते से भी अधिक समय के बाद भी मलबे के भीतर से शव बरामद हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या 41,000 के आंकड़े को पार कर गई है, दक्षिणी तुर्की में मलबे के नीचे से अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं, और अधिक जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद की एक हल्की किरण की पेशकश कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, नौ लोगों को मंगलवार को तुर्की में मलबे से बचाया गया था और सहायता प्रयास का ध्यान अब आश्रय या पर्याप्त भोजन के बिना संघर्ष कर रहे लोगों की मदद करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है।सोमवार को दोनों देशों से मरने वालों की संख्या 37,000 से अधिक हो गई, जिससे यह इस सदी की दुनिया की सबसे खराब प्राकृतिक आपदाओं और 1939 के बाद से तुर्की के सबसे घातक भूकंपों में से एक बन गया।संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने जो आशंका जताई है वह और दिल दहलाने वाला है। दरअसल, मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि इस विनाशकारी भूकंप में 50 हजार से अधिक लोगों की जान गई होगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैंने मृतकों की संख्या गिनना शुरू नहीं किया है लेकिन जिस तरह से मलबे दिख रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि यह आंकड़ा 50 हजार से अधिक जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही, खोज और बचाव लोग मानवीय एजेंसियों के लिए रास्ता बनाएंगे, जिनका काम अगले महीनों के लिए प्रभावित लोगों की असाधारण संख्या को देखना होगा।

रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में 6000 यूक्रेनी बच्चे कैद

सियासी शिक्षा के जरिए 'ब्रेनवॉश' करने की कोशिश

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में लगभग 6,000 यूक्रेनी बच्चों को कैद होने की खबर सामने आ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक यूएस समर्थित रिपोर्ट के हवाले से इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार, इन बच्चों को पालने का उद्देश्य उन्हें पुतिन की सेना के द्वारा राजनीतिक शिक्षा देकर ब्रेनवॉश करना हो सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कम से कम 43 शिविरों और सुविधाओं की पहचान की है जहां यूक्रेनी बच्चों को रखा गया है जो यूक्रेन पर फरवरी 2022 के आक्रमण के बाद से मास्को द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर व्यवस्थित नेटवर्क का हिस्सा थे। शोधकर्ताओं में से एक नथानिएल रेमंड ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से बताया कि हमने जिन शिविर सुविधाओं की पहचान की है, उनका प्राथमिक उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा देकर ब्रेनवॉश करने की कोशिश है। बच्चों में माता-पिता या स्पष्ट पारिवारिक संरक्षकता वाले लोग शामिल थे, जिन्हें रूस ने अनाथ माना था। अन्य बच्चे वे थे जो आक्रमण से पहले यूक्रेनी राज्य संस्थानों की देखभाल में थे और जिनकी हिरासत युद्ध के कारण अस्पष्ट या अनिश्चित थी। इस बीच, यूक्रेनी अभियोजकों ने कहा है कि वे रूस के खिलाफ नरसंहार अभियोग बनाने के प्रयासों के तहत बच्चों के जबरन निर्वासन के आरोपों की जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिविरों की प्रणाली और रूसी परिवारों द्वारा अपनी मातृभूमि से लिए गए यूक्रेनी बच्चों को गोद लेना रूस की सरकार का सबसे क्रूर चेहरा प्रतीत होता है।

दक्षिण और मध्य एशिया में आतंकी खतरे का प्रमुख स्रोत बना अफगानिस्तान

नई दिल्ली(वेब वार्ता)।संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान ही आतंकवाद का केंद्र रहेगा और यहीं से ही मध्य और दक्षिण एशिया तक अशांति रह सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी और सुरक्षा की लचर व्यवस्था के चलते आईएसआईएल-खुरासान, अल कायदा और तहरीक ए तालिबान जैसे आतंकी संगठन वहां आराम से अपनी जड़े जमाए हुए हैं। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की 31वीं एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन्स मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। यह रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और लेवैंट-खुरासान, अल-कायदा, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, इस्लामिक जिहाद ग्रुप, खतिबा इमाम अल बुखारी, खतिबा अल तौहीद वल-जिहाद, जमात अंसारुल्लाह और अन्य कई आतंकी अफगानिस्तान से शुरू हुए हैं और इन आतंकी संगठनों को अफगानिस्तान में पूरी आजादी मिली हुई है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में अब सुरक्षा व्यवस्था भी काफी लचर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान को अफगानिस्तान में आईएस-खुरासान से कड़ी चुनौती मिल रही है। खुरासान अफगानिस्तान के लोगों के यह अहसास कराना चाहता है कि तालिबान उन्हें सुरक्षा देने में नाकाम हो रहा है और इसी लिए खुरासान संगठन अफगानिस्तान में हमलों को अंजाम दे रहा है। आईएस-खुरासान अन्य देशों के साथ तालिबान के रिश्तों को भी कमजोर करना चाहता है। बीते दिनों कई दूतावासों पर हुए हमलों में भी खुरासान गुट का नाम सामने आया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि खुरासान गुट चीन, पाकिस्तान और भारत में भी आतंकी हमले करने की तैयारी कर रहा है।आईएस-खुरासान में आतंकियों की संख्या करीब छह हजार बताई जा रही है और यह अफगानिस्तान के कुनार, नांगरहर और नूरीस्तान जैसे प्रांतों में सक्रिय है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल कायदा की ताकत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। अल जवाहिरी की मौत के बाद भी अल कायदा अफगानिस्तान में अपनी जगह बनाए हुए है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता कब्जाने के बाद तहरीक ए तालिबान की भी ताकत में इजाफा हुआ है। जिसके बाद से यह आतंकी संगठन पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है।

ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ भारत टेस्ट में बना नंबर वन

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। भले ही ऊ20 विश्वकप के सेमीफाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया की खूब आलोचना हुई थी। लेकिन 2023 के दूसरे महीने में ही टीम इंडिया ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की ओर से क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की ताजा रैंकिंग जारी की गई है। अब भारत क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर वन टीम बन गया है। भारत ने टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर वन का ताज हासिल किया है। नागपुर में भारत को मिली एकतरफा जीत से टीम इंडिया को बड़ा फायदा हुआ है। नागपुर टेस्ट के बाद यह पहला मौका है, जब रैंकिंग अपडेट हुई है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही साथ तीनों ही फॉर्मेट में भारत की टीम नंबर वन बनी है। भारतीय टीम ऊ20 और एकदिवसीय फॉर्मेट में पहले से ही नंबर वन पर थी। ऐसे में नागपुर में मिली बंपर जीत के बाद टेस्ट में भी टीम इंडिया नंबर वन पर पहुंच गई है। नागपुर में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक पारी और 132 रनों से हराया था। भारत की टीम पहली बार टेस्ट में 1973 में नंबर 1 बनी थी। इसके बाद टेस्ट में नंबर एक पर पहुंचने के लिए टीम इंडिया को लंबा इंतजार करना पड़ा। 2009 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया टेस्ट में नंबर वन पर पहुंची थी। 2011 तक भारत टॉप पर रहा। इसके बाद विराट कोहली की अगुवाई में 2016 में टीम इंडिया ने टेस्ट में नंबर वन की रैंकिंग हासिल की। 2020 तक भारत इस रैंकिंग पर काबिज रहा। तब से टीम इंडिया लगातार टॉप 3 की टीमों में शामिल थी। अब एक बार फिर से नंबर एक पर पहुंच गई है। टेस्ट रैंकिंग की बात की जाए तो भारत के पास 115 रेटिंग अंक है। ऑस्ट्रेलिया 111 के साथ दूसरे, इंग्लैंड 106 के साथ तीसरे पोजीशन पर है। वनडे भारत में 114 रेटिंग के साथ पहले पायदान पर है। दूसरे पर 112 के साथ ऑस्ट्रेलिया है जबकि 111 के साथ तीसरे पर न्यूजीलैंड है। ऊ20 की बात करें तो यहां भारत के खाते में 267 रेटिंग हैं। टीम इंडिया नंबर वन पर है जबकि दूसरे पायदान पर इंग्लैंड की टीम 266 अंक के साथ है। पाकिस्तान के खाते में 258 अंक हैं।

मेसी की पीएसजी और टोटेनहम को मिली हार

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। चैंपियंस लीग में अंतिम-16 राउंड की शुरुआत दो बड़े मैचों के साथ हुई। लियोनल मेसी की पीएसजी को बायर्न म्यूनिख के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं, एसी मिलान ने टोटेनहम को 1-0 के अंतर से हराया। बायर्न म्यूनिख ने पीएसजी के खिलाफ शुरुआत से ही बेहतरीन खेल दिखाया, लेकिन पहले हाफ तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकीं। इसके बाद जोआ कैंसेलो की जगह अलफोंसो डेविस को मैदान में भेजा गया और उन्होंने मैदान में जाते ही अपनी पुरानी टीम के खिलाफ गोल करने में मदद की। डेविस की मदद से किंग्सले कोमन ने मैच का एकमात्र गोल किया। चोट से वापस लौटे किलियन एम्बाप्पे ने बेहतरीन गोल कर मैच में अपनी टीम को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वीएआर रिव्यू में उनका गोल अमान्य करार दिया गया। मेसी, नेमार और एम्बाप्पे जैसे स्टार खिलाड़ियों से भरी पेरिस सेंट जर्मन की टीम को भले ही इस मैच में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस टीम ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है और आगे भी पीएसजी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। बायर्न म्यूनिख के बेंजामिन पावर्ड को इस मैच में दो येलो कार्ड मिले। उन्होंने मेसी के खिलाफ दूसरा फाउल किया और वह अगले मैच में नहीं खेल पाएंगे। उन्हें मेसी पर फाउल करने के साथ ही मैदान से बाहर कर दिया गया था।

आरसीबी ने बेन सॉयर को बनाया महिला टीम का कोच

माइक हेसन को मिली बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली (वेब वार्ता)।रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चार मार्च से शुरू होने वाली विमेंस प्रीमियर लीग (ड्रप्) के ऑस्ट्रेलिया के बेन सॉयर को मुख्य कोच बनाया है। बेन सॉयर न्यूज़ीलैंड के रहने वाले हैं और वह अपने देश की राष्ट्रीय महिला टीम के भी कोच हैं। वह आरसीबी में अपने देश की कप्तान सोफी डिवाइन के साथ जुड़ेंगे। डिवाइन को आरसीबी ने नीलामी में 50 लाख रुपये में खरीदा था।बेन सॉयर ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं। उनकी कोचिंग में सिडनी सिक्सर्स की टीम 2016-17 और 2017-18 सीजन में लगातार दो बार महिला बीबीएल ट्रॉफी जीती थी। सॉयर के साथ-साथ न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हेसन टीम के क्रिकेट डायरेक्टर होंगे। वह आरसीबी की पुरुष टीम के भी क्रिकेट डायरेक्टर हैं।स्काउटिंग के प्रमुख मलोलन रंगराजन को सहायक कोच नियुक्त किया गया है। भारत की पूर्व सलामी बल्लेबाज वनिता वीआर को टीम का फील्डिंग कोच नामित किया गया है। वह स्काउटिंग टीम का हिस्सा थीं। आरएक्स मुरली को 2023 सीजन के लिए टीम के बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। विमेंस प्रीमियर लीग के पहले सीजन के लिए खिलाड़ियों की नीलामी सोमवार (13 फरवरी) को मुंबई में हुई। आरसीबी 18 खिलाड़ी खरीदे। उसने भारत की स्मृति मंधाना, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी, मेगन सुट, न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन, इंग्लैंड की हीथर नाइट और दक्षिण अफ्रीका की डेन वान निकर्क को खरीदकर एक मजबूत टीम तैयार की है।आरसीबी ने 18 खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 11.90 करोड़ रुपये खर्च किए। उसके पर्स में 10 लाख रुपये शेष रह गए। आरसीबी ने स्मृति मंधाना के लिए सबसे ज्यादा 3.40 करोड़ रुपये खर्च किए। मंधाना इस नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी रहीं। आरसीबी ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष के लिए भी बड़ी रकम खर्च की। ऋचा को आरसीबी ने 1.90 करोड़ रुपये में खरीदा।

टेनिस से सन्यास लेने के बाद महिला क्रिकेट की आरसीबी से जुड़ी सानिया मिर्जा

बेंगलुरु (वेब वार्ता)। पिछले महीने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना आखिरी ग्रैंडस्लैम टूर्नामेंट खेलने वाली भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की टीम ने आगामी महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के लिए अपना मार्गदर्शक बनाया है। आरसीबी के एक बयान में छह ग्रैंडस्लैम और 43 डब्ल्यूटीए खिताब जीतने वाली सानिया ने कहा कि आरसीबी महिला टीम से मार्गदर्शक के रूप में जुड़ना मेरे लिए खुशी की बात है।'' उन्होंने कहा, ''भारतीय महिला क्रिकेट ने महिला प्रीमियर लीग के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा है और मैं वास्तव में इस क्रांतिकारी कदम का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं।''सानिया ने कहा, ''आरसीबी आईपीएल में एक लोकप्रिय टीम और वर्षों से बहुत अधिक फॉलो की जाने वाली टीम रही है। मैं उन्हें महिला प्रीमियर लीग के लिए एक टीम बनाते हुए देखकर बेहद खुश हूं।'' उन्होंने कहा, ''यह देश में महिलाओं के क्रिकेट को नई ऊंचाइयों

तक ले जाएगा। महिला क्रिकेटरों के लिए नए दरवाजे खोलेगा और खेल को युवा लड़कियों और युवा माता-पिता के लिए करियर की पहली पसंद बनाने में मदद करेगा।'' सानिया ने इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बाद टेनिस से संन्यास ले लिया जहां वह और उनके साथी रोहन बोपन्ना मिश्रित युगल स्पर्धा में उपविजेता रहे।आरसीबी ने 18 खिलाड़ियों को शामिल करते हुए एक मजबूत टीम बनाई है जिसमें महिला क्रिकेट के कुछ बड़े नाम जैसे स्मृति मंधाना, ऑस्ट्रेलिया की एलिस पैरी और मध्यम तेज गेंदबाज मेगन शुट, न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन, इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट, दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर डेन वान नीकर्क और भारत की अंडर-19 स्टार रिचा घोष शामिल हैं।

टेस्ट रैंकिंग में फिर शीर्ष पर पहुंचने के करीब अश्विन

नई दिल्ली (वेब वार्ता)।ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी रैंकिंग में भी फायदा मिला है। रविचंद्रन अश्विन ने इस मैच में आठ विकेट अपने नाम किए थे और गेंदबाजों की रैंकिंग में वह शीर्ष पर पहुंचने के करीब हैं। अश्विन फिलहाल दूसरे स्थान पर हैं और शीर्ष पर काबिज पैट कमिंस से 21 रेटिंग प्वाइंट पीछे हैं। उनके पास 2017 के बाद फिर से टेस्ट में नंबर एक गेंदबाज बनने का मौका है। अश्विन के अलावा रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल और रोहित शर्मा को भी आईसीसी रैंकिंग में फायदा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने नागपुर टेस्ट में खराब प्रदर्शन किया था। इसका खामियाजा डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा को उठाना पड़ा है।नागपुर टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया था और दोनों ने मिलकर 15 विकेट झटके थे। इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही भारत यह मैच पारी और 132 रन से जीतने में सफल रहा था। अश्विन ने पहली पारी में 42 रन देकर तीन विकेट और दूसरी पारी में 37 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए थे। वहीं, जडेजा ने पहली पारी में 47 रन देकर पांच विकटे लिए थे। इसमें स्मिथ और

मार्नस लाबुशेन के कीमती विकेट भी शामिल थे। दूसरी पारी में जडेजा ने 34 रन देकर दो विकेट झटके।वेस्टइंडीज के गुदाकेश मोती ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दो टेस्ट में 19 विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है और 77 स्थान की छलांग के साथ गेंदबाजों की रैंकिंग में 46वें स्थान पर आ गए हैं। उन्होंने अपने करियर में अब तक सिर्फ तीन टेस्ट खेले हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी नागपुर में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 120 रन की शानदार पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के 177 रन पर सिमटने के बाद रोहित के 120 रन की पारी के चलते भारत को अहम बढ़त मिली थी। रोहित की इसी पारी ने भारत की जीत तय की। रोहित को दो स्थान का फायदा हुआ है और बल्लेबाजों की रैंकिंग में वह आठवें स्थान पर आ गए हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा पूरी तरह फेल रहे थे और दोनों को बल्लेबाजों की रैंकिंग में नुकसान हुआ है।

एशियन मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप 2023 में भारत की विजयी शुरुआत

दुबई (वेब वार्ता)। भारत ने स्टार शटलर पीवी सिंधू और एचएस प्रणय की आसान जीत से मंगलवार को यहां ग्रुप मैच में कजाकिस्तान को 5-0 से करारी शिकस्त देकर एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। ईशान भटनागर और तनिशा क्रैस्टो की मिश्रित युगल जोड़ी ने मखसुत तदज़ीबुल्लाएव और नर्गिजा रख्मेतुल्लायेवा को 21-5 21-11 से हराकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद प्रणय ने पुरुष एकल में केवल 24 मिनट में दिमित्रि पनारिन

को 21-9 21-11 से हराया। सिंधू ने इसके बाद कामिला स्मागुलोवा को केवल 20 मिनट में 21-4 21-12 से हराकर भारत को 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी। कृष्ण प्रसाद गरगा और विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला की दूसरी मिश्रित युगल जोड़ी और त्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला युगल जोड़ी ने भी अपने-अपने मैच सीधे गेम में जीते।भारत अपने दूसरे ग्रुप बी मैच में बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात से भिड़ेगा। मलेशिया ग्रुप की अन्य टीम है। टीमों को चार ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक ग्रुप में चार-चार टीम शामिल हैं। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

त्रिपुरा में चुनावी घमासान थमा, पक्ष-विपक्ष में कांटे की टक्कर

त्रिपुरा/अगरतला। नार्थ ईस्ट के प्रमुख केन्द्र त्रिपुरा में चुनावी सरगर्मी अब शांत हो गयी है और सारे प्रमुख दलों और स्थानीय पार्टियों के प्रचार थम गये हैं और मतदान के लिए सभी पार्टियों ने पुरजोर प्रयास करते हुए अपनी मंजिल तय करने का प्रयास किया है।

हमारे अगरतला प्रतिनिधि से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार का चुनाव त्रिपुरा में काफी अलग दिखा क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जहां विपक्ष पूरी जुगलबंदी करते हुए चुनाव में सत्तासीन पार्टी को धूलचटाने के लिए अपने स्टार प्रचारकों से लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं की टीम को पूरी सुनियोजित तरीके से उतरा था और बूथ वाइज कैंम्पिंग करते हुए मतदाओं को अपनी मोड़ने का प्रयास करते हुए हर हथकंडे का उपयोग किया हैं । विपक्षी दलों में प्रमुख रूप से सीपीएम , त्रिपुरामोथा मोर्चा आंचलिक पार्टी , त्रिणमूल कांगेस और कांग्रेस का चुनाव के अन्तिम दोर में अथक प्रयास करते हुए एक बार पुनः सत्ता में वापसी का प्रयास किया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी को चुनाव प्रचार में उतारते हुए जनता का यह बताने का प्रयास किया कि त्रिपुरा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में यदि कोई पार्टी जनता की कसौटी पर खरा उतर रही है तो वह है भारतीय जनता पार्टी जिसने जनता की समस्यओं को गंभीरता से लेते हुए उसकी समस्यओं के निदान का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री तक द्वारा अपील की गयी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना अमन चैन है और विकास हुआ है वह बीत सत्तर सालों में नहीं हो पाया हैं। भारतीय जनता पाटी ने प्रधानमंत्री आवास से लेकर देश की सभी गरीब जनता को निःशुल्क राशन और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आयुष्यमान योजना जिसमें बगैर किसी भेदभाव के लोगों को लाभान्वित कराने का प्रयास किया गया। यही नहीं प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने त्रिपुरा और नार्थ ईस्ट के अन्य प्रांतों का हवाला देने हुए कहा कि पहले क्षेत्र में गरीबों को किस प्रकार सताया जता था और क्षेत्र में नक्सलवाद कितनी तेजी से पांव पसार रहा था लेकिन भारतीय जतना पार्टी की सरकार जब से बनी है जब से उसने नक्सवाद ओर आतंकवाद की रीढ़ को तोड़कर नेस्तोनाबूद करने का कार्य किया है और देश के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव को जीन का अधिकार दिया है।

विपक्ष और सत्ता पक्ष ने अपने स्तर से जनता को चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास और बहुत सारे लुभावने नारे देते हुए उसे अपनी ओर आकर्षित करने का पुरजोर प्रयास किया है लेकिन देखना यह है कि जनता किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है। हलॉकि ने भारतीय जनता पार्टी ने अन्त समय में हिन्दू ट्रम्पकार्ड खेलते हुए प्रधानमंत्री आवास और गरीब जनता की मूलभूत समस्यओं को आधार बनाते हुए बड़ा तीखा प्रहार किया है जिससे विपक्ष अपने को हतोत्साहित महसूस करने लगा है । यदि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों की बात जनता के समझ में आयी और भाजपा के आकांओं द्वारा प्रोफेसर मानिक शाह को गरीबों का मशीहा बताने का प्रयास करते हुए दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास और बहुत सारी अयोजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है उससे लगता है कि प्रदेश में एक बार पुनः त्रिपुरा में भाजपा की सरकार बनना तय है क्योंकि इससे पहले त्रिपुरा में इतना विकास हुआ था और न ही इतनी योजनओं का शिलान्यास ही हुआ था इसलिए जनता को पूर्ण विश्वास है कि यदि इस बार दुबार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रदेश का बहुमुखी विकास होना तय है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी जिस प्रकार से त्रिपुरा की छोटी-छोटी घटनाओं पर पैनी नजर रखते हुए विशेषकर आदिवासी मतों का ध्रूवीकरण करते हुए अपने पक्ष में मतदान करने का प्रयास किया है। और दलित पिछड़ों के साथ ही मुश्किलमों की समस्यओं को नजरअंदाज करके कुछ अपने चहेतों को लाभ पहुॅचाने की बात जनता तक पहुॅचाते हुए मतदाताओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। यही नहीं चर्चाओं की माने तो विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री विपल्ब कुमार देब और प्रोफेसर डा0 मानिकशाह के सम्बंधों में एक दूसरे के खटास के नजरिये से देखते हुए मतदाओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। कई पिछड़े क्षेत्रों में विपक्ष को इसका सीधा फायदा भी मिलता दिखा है। यह बात अलग है कि यह मतदान स्थल तक पहुॅचने तक कितना सफल हो पाता है यह तो वाला कल है ही बतायेगा। त्रिपुरा में इस बार भाजपा की वापसी हो पायेगी या विपक्ष उसके मंसूबों पर पानी फेरते हुए एक बार पुनः सत्तासीन हो पायेगा यह कहपाना अभी जल्दबाजी होगी।

त्रिपुरा राज्य के आठ जिलों में होने वाले इस बार के चुनाव में कई बिधानसभा सीटों पर त्रिकोणात्मक तो कहीं चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है जबकि कुछ सीटों पर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल रही है।

कैबिनेट ने दी आईटीबीपी की सात नई बटालियन को मंजूरी

नई दिल्ली (वेब वार्ता)। मोदी कैबिनेट ने बुधवार को देश की सुरक्षा को लेकर कई बड़े व अहम फैसले किए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, कैबिनेट ने भारत-चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के लिए 9,400 कर्मियों की एक ऑपरेशनल बटालियन के साथ सात नई बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सिंकुलना टनल के निर्माण को भी मंजूरी दे दी गई। इस टनल के निर्माण से लद्दाख के लिए ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी। टनल की लंबाई 4.8 किलोमीटर होगी, जिस पर 1800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस

टनल के निर्माण से दुर्गम क्षेत्रों में सैन्य बलों की पहुंच बढ़ेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने देश में सहकारिता आंदोलन की जमीनी स्तर तक पहुंच को मजबूत करने के लिए लिए भी समितियों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया, अगले पांच सालों में दो लाख बहुउद्देशीय डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

सीएम योगी ने किया आयुष विवि की ओपीडी सेवा का शुभारंभ

गोरखपुर (वेब वार्ता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने भटहट के पिपरी में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनपदवासियों को बधाई देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय का लाभ सबसे अधिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगी। सीएम ने कहा कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति के माध्यम से विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को कल से देखना प्रारंभ कर देंगे। इसका लाभ भटहट, चरगांवा, पिपराइच, परतावल, पनियारा और गोरखपुर जनपद के सभी वासियों को तथा महाराजगंज वासियों को प्राप्त होने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की ओर बढ़ चुका है। पहले केवल गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सिद्धार्थनगर, बस्ती, महराजगंज, संतकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, बहराइच के साथ ही नेपाल के सभी लोगों को व बिहार के लोगों को आना होता था। लेकिन, आपने अच्छी सरकार चुनी और केंद्र में मोदी जी ने अपना आशीर्वाद

दिया।प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई आज परिणाम है गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज जो बंदी की कगार पर था उसमें सुपर स्पेशियलिटी की स्थापना हो रही है। गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो गई है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। देवरिया में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो चुका है। महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज के कार्य प्रारंभ होने वाला है। सिद्धार्थनगर में भी प्रारंभ हो चुका है।बता दें कि मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। गुरुवार की दोपहर क्षेत्रीय क्रीड़ांगन में आयोजित सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में उपस्थित रहेंगे। जीडीए की सफाई व्यवस्था में शामिल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे ।योगी सरकार विश्व की सबसे पुरातन भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी को बढ़ावा दे रही है। इस पैथी का कोई साइड इफेक्ट न होने से लोगों में इसे लेकर भरोसा ज्यादा है। आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ) को प्रोत्साहित करने तथा इनका लाभ लोगों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर भटहट के पिपरी में पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है।

अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता रद्द

स्वार सीट हुई रिक्त, कोर्ट ने छजलैट मामले में सुनाई है दो साल की सजा

लखनऊ(वेब वार्ता)।सपा नेता आजम खां के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है। बता दें कि पंद्रह साल पुराने छजलैट प्रकरण में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को अदालत दो साल की सजा सुनाई है। दोनों पर तीन-तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस मामले में अन्य सात आरोपी साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिए गए। जानकारों के अनुसार दो साल की सजा के कारण स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाती रहेगी। पूर्व में रामपुर की अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद नगर सीट से आजम खां की विधायकी जा चुकी है। 2 जनवरी 2008 पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे।इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि आम जनता को उकसा कर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।इस मामले में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर की

नूरपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नईम ऊल हसन, नगीना से सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, राजेश यादव, डीपी यादव, पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति को आरोपी बनाया गया था। इस केस की सुनवाई वर्ष 2019 से मुरादाबाद की एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट स्मृति गोस्वामी की कोर्ट में की जा रही थी। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि अदालत पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दो-दो साल की सजा सुनाई है और तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।जबकि मुरादाबाद देहात विधान सभा क्षेत्र से पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी, बिजनौर की नूरपुर विधानसभा सीट के पूर्व विधायक नईम ऊल हसन, नगीना से सपा विधायक मनोज पारस, अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, राजेश यादव, डी पी यादव,पूर्व महानगर अध्यक्ष राजकुमार प्रजापति को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।

सम्पादक : राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

कार्यालय : 190K /2H/1R ओपीएस नगर
राजरुपपुर प्रयागराज-211011

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्रीमती आशा श्रीवास्तव द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज, विष्णुपदम कुटीर,115डी/2ई, लूकरगंज प्रयागराज से मुद्रित कराकर 190K/2H/1R ओपीएस नगर राजरुपपुर, प्रयागराज से प्रकाशित।

दूरभाष : 09336664852, 09450607846

email: rajendranyaypath@gmail.com

R.N.I. No. - UPHIN/2010/36184

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी0आर0बी0 एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इससे समस्त विवादो का निबटारा इलाहाबाद न्यायालय के अधीन ही होंगे।